राजेंद्र प्रह्लादराव वासनिक

बनाम

महाराष्ट्र राज्य

(समीक्षा याचिका (आपराधिक) संख्या 306-307/2013)

में

(आपराधिक अपील संख्या 145-146/2011)

12 दिसंबर 2018

[मदन बी. लोकुर, एस. अब्दुल नज़ीर और दीपक गुप्ता, जे.जे.]

आपराधिक न्याय प्रशासन - मृत्युदंड - विचार किए जाने वाले कारक - अपीलकर्ता को 3 साल की बच्ची के बलात्कार और हत्या के लिए दोषी ठहराया गया - अपीलकर्ता को दी गई मृत्युदंड की सजा की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा की गई - अपीलकर्ता द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की गई कोर्ट ने खारिज की- रिव्यू याचिकाएं भी खारिज हालांकि, मोहम्मदाबाद मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले के मद्देनजर रिव्यू याचिकाएं बहाल हो गईं। आरिफ उर्फ अशफाक मामला-अभिनिर्धारित: आमतौर पर, परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में मौत की सजा देना उचित नहीं होगा - लेकिन ऐसा कोई सख्त नियम नहीं है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में मौत की सजा नहीं दी जानी चाहिए - अगर अदालत रिकॉर्ड पर मौजूद परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर कुछ संदेह है कि आरोपी ने अपराध नहीं किया होगा, तो बरी करने का मामला बनाया जाएगा - यदि अदालत मौत की सजा देने के लिए इच्छुक है तो कुछ असाधारण परिस्थितियां होनी चाहिए। अत्यधिक जुर्माना लगाना इस

मामले में, आरोपी के शरीर से नमूने लिए गए और डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए भेजे गए, हालांकि, परिणाम ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया - इसके लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है। डीएनए साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर, इस मामले के तथ्यों के आधार पर, अपीलकर्ता की मौत की सजा को बरकरार रखना खतरनाक होगा। इसके अलावा, संभावना (निष्क्रियता या असंभवता या असंभवता नहीं) कि एक दोषी को सुधारा जा सकता है और समाज में उसका पुनर्वास किया जा सकता है। मौत की सज़ा देने से पहले अदालतों द्वारा इस पर गंभीरता से विचार किया जाता है - अभियोजन पक्ष का यह दायित्व है कि वह सबूतों के माध्यम से यह साबित करे कि इसकी संभावना क्या है दोषी को सुधारा या पुनर्वासित नहीं किया जा सकता - सजा सुनाने के प्रयोजनों के लिए, सत्र न्यायाधीश, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने सुधार की संभावना पर विचार नहीं किया। अपीलकर्ता का पुनर्वास और समाज में पुनः एकीकरण - इसके अलावा, ट्रायल कोर्ट ने भी विचार करने में गलती की। सजा के प्रयोजनों के लिए, अपीलकर्ता के खिलाफ दो समान मामलों की लंबितता, जिस पर वह कानून में विचार नहीं कर सकता था - हालांकि, अपीलकर्ता द्वारा किए गए अपराधों और उसके समग्र व्यक्तित्व और उसके बाद की घटनाओं सहित रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री को देखते हुए, सजा सुनाई जाएगी। अपीलकर्ता को दी गई मौत की सज़ा कम कर दी गई है लेकिन अपीलकर्ता को उसके शेष सामान्य जीवन के लिए हिरासत से रिहा नहीं किया जाना चाहिए-दंड संहिता, 1860 - धारा 376 (2) (एफ), 377 और 302- साक्ष्य अधिनियम, 1872 - धारा 54 - सीआर.पी.सी, 1973 - धारा 354।

साक्ष्य-डीएनए-फोरेंसिक विज्ञान-का महत्व - अभिनिर्धारित किया: डीएनए प्रोफाइलिंग नमूनों की तुलना करने का एक बेहद सटीक तरीका है और इस तरह के परीक्षण से लगभग सकारात्मक पहचान हो सकती है- जहां डीएनए प्रोफाइलिंग नहीं की

गई है या इसे ट्रायल कोर्ट से रोका गया है, एक अभियोजन के लिए प्रतिकूल परिणाम होंगे - सीआर.पी.सी. 1973-धारा 53-ए, 164-ए।

सजा की सजा-दोषी का पूर्व इतिहास या आपराधिक पृष्ठभूमि - यदि विचार किया जाए: किसी दोषी के खिलाफ केवल एक या एक से अधिक आपराधिक मामलों का लंबित होना सजा देते समय विचार के लिए एक कारक नहीं हो सकता है - न केवल यह वैधानिक रूप से अस्वीकार्य है (सिवाय इसके कि) कुछ मामलों में) लेकिन अन्यथा भी यह निर्दोषता की मौलिक धारणा - एक मानव अधिकार - का उल्लंघन करता है जिसका हर कोई हकदार है।

समीक्षा याचिकाओं का निपटारा करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1.1. सामान्यतः, परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में मृत्युदंड देना उचित नहीं होगा। लेकिन ऐसा कोई सख्त नियम नहीं है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में मौत की सज़ा नहीं दी जानी चाहिए। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामलों में सभी अदालतों द्वारा बरती जाने वाली सावधानियां इस प्रकार हैं: यदि अदालत को रिकॉर्ड पर परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर कुछ संदेह है, कि अभियुक्त ने अपराध नहीं किया होगा, तो बरी करने का मामला बनाया जाएगा। बाहर; यदि न्यायालय को परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर कोई संदेह नहीं है कि अभियुक्त दोषी है, तो निश्चित रूप से एक दृढ़ विश्वास का पालन करना होगा। यदि अदालत मौत की सज़ा देने के लिए इच्छुक है तो कुछ असाधारण परिस्थितियाँ होनी चाहिए जो अत्यधिक सज़ा देने के लिए आवश्यक हों। ऐसे मामलों में भी, अदालत को बचन सिंह मामले में दी गई उक्ति का पालन करना चाहिए कि न केवल अपराध, बल्कि अपराधी को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए और सजा का कोई भी वैकल्पिक विकल्प निर्विवाद रूप से बंद है। दूसरी सावधानी का कारण

यह है कि फाँसी पर मौत की सज़ा अपरिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय है। [पैरा 29] [606-सी-एफ]

सुधार, पुनर्वास और समाज में पुनः एकीकरण

1.2. किसी दोषी को सुधारा जा सकता है और समाज में उसका पुनर्वास किया जा सकता है, इसकी संभावना (संभावना या असंभाव्यता या असंभाव्यता नहीं) पर मौत की सजा देने से पहले अदालतों को गंभीरता से और ईमानदारी से विचार करना चाहिए। यह सीआरपीसी की धारा 354(3) की "विशेष कारणों" की आवश्यकता के आदेशों में से एक है। और इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति का जीवन बर्बाद करना शामिल है। इस आदेश को क्रियान्वित करने के लिए, अभियोजन पक्ष का यह दायित्व है कि वह साक्ष्य के माध्यम से अदालत को यह साबित करे कि संभावना यह है कि दोषी को सुधारा या पुनर्वासित नहीं किया जा सकता है। इसे अन्य बातों के साथ-साथ, जेल में उसके आचरण, जेल के बाहर उसके आचरण, यदि वह कुछ समय के लिए जमानत पर है, के बारे में चिकित्सा साक्ष्य, उसकी मानसिक स्थिति, उसके परिवार के साथ संपर्क आदि के बारे में सामग्री लाकर हासिल किया जा सकता है। इसी तरह दोषी इन मुद्दों पर भी सबूत पेश कर सकता है। [पैरा 4511612-डी-एफ]

1.3. यदि इस प्रकृति की जांच की जानी है, जैसा कि इस न्यायालय के निर्णयों द्वारा अनिवार्य है, तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि दोषसिद्धि की तारीख और सजा देने की तारीख के बीच की अवधि पार्टियों को इकट्ठा करने में सक्षम बनाने के लिए काफी लंबी होगी और ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करें जो ट्रायल कोर्ट को सज़ा पर उचित निर्णय लेने में सहायता कर सकें। लेकिन, इस संबंध में कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि किसी भी मामले में दोषी काफी लंबे समय तक हिरासत में रहेगा और कम से कम उम्रकैद की सजा काटेगा। यह निर्धारित करना अभियोजन और अदालतों का काम है कि क्या ऐसे

व्यक्ति को, उसके अपराध के बावजूद, सुधार और पुनर्वास किया जा सकता है। इस जानकारी को प्राप्त करना और उसका विश्लेषण करना निश्चित रूप से एक आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी इसे किया जाना चाहिए। की प्रक्रिया पुनर्वास भी आसान नहीं है क्योंकि इसमें दोषी का समाज में सामाजिक पुन:एकीकरण शामिल होता है। बेशक, उपलब्ध कराई गई किसी भी जानकारी और रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों के साथ विशेषज्ञों द्वारा उसके विश्लेषण के बावजूद, ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जहां दोषी का सामाजिक पुन: एकीकरण संभव नहीं हो सकता है। यदि ऐसा होना चाहिए, तो लंबी अवधि के कारावास का विकल्प स्वीकार्य है। [पैरा 46, 47] [612-एफ-जी: 613-डी-ई]

1.4 दूसरे शब्दों में, 14 वर्ष (जैसे 20 या 25 वर्ष) से अधिक की अवधि के लिए कारावास का निर्देश देना निर्विवाद रूप से मौत की सजा देने से रोक सकता है, जो मृत्युदंड का एक वैकल्पिक विकल्प है। [पैरा 48][613-ई-एफ]

डीएनए साक्ष्य

2.1 जबकि सीआरपीसी की धारा 53-ए यह अनिवार्य नहीं है, इसके लिए निश्चित रूप से एक सकारात्मक निर्णय लेने की आवश्यकता है। यह विश्वास करने के लिए उचित आधार होना चाहिए कि किसी व्यक्ति की जांच से बलात्कार के अपराध के घटित होने या बलात्कार करने के प्रयास के सबूत मिलेंगे। यदि उचित आधार मौजूद हैं, तो सीआरपीसी की धारा 53-ए(2) के अनुसार एक चिकित्सा जांच की जाएगी। आयोजित किया जाना चाहिए और इसमें आरोपी की जांच और डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए आरोपी के व्यक्ति से ली गई सामग्री का विवरण शामिल है। इसी प्रकार सीआरपीसी की धारा 164-ए. जहां भी संभव हो, बलात्कार की पीड़िता की चिकित्सीय जांच की आवश्यकता होती है। बेशक, पीड़ित की सहमति आवश्यक है और परीक्षा आयोजित करने वाला

व्यक्ति पीड़ित की चिकित्सकीय जांच करने में सक्षम होना चाहिए! [पैरा 49, 50] [613-एफ-एच; 614-ए, बी-सी]

2.2 अभियोजन पक्ष के लिए डीएनए साक्ष्य प्रस्तुत करने से इनकार करना थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा, खासकर जब देश में डीएनए प्रोफाइलिंग की सुविधा उपलब्ध है। अभियोजन पक्ष को इसका लाभ उठाने की सलाह दी जाएगी, खासकर सीआरपीसी की धारा 53-ए और धारा 164-ए के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए। यह सुझाव दिया जा रहा है कि यदि कोई डीएनए प्रोफाइलिंग नहीं है, तो अभियोजन पक्ष का मामला साबित नहीं किया जा सकता है, लेकिन निश्चित रूप से जहां डीएनए प्रोफाइलिंग नहीं की गई है या इसे ट्रायल कोर्ट से रोक दिया गया है, अभियोजन पक्ष के लिए प्रतिकूल परिणाम होगा। [पैरा 54] [615-जी-एच: 616-ए]

2.3 इसमें कोई विवाद नहीं है कि आरोपी के शरीर से नमूने लिए गए और डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए भेजे गए। हालाँकि, परिणाम ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसके लिए बिल्कुल कोई स्पष्टीकरण नहीं है और डीएनए सबूत पेश न करने के किसी औचित्य के अभाव में, इस मामले के तथ्यों के आधार पर, अपीलकर्ता को मौत की सजा बरकरार रखना खतरनाक होगा। [पैरा 57] [616-एफ-एच]

दोषी का पूर्व इतिहास या आपराधिक इतिहास

3.1 दोषी का इतिहास, जिसमें दोबारा अपराध करना भी शामिल है, मौत की सज़ा देने का आधार नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति हो सकती है जहां किसी दोषी ने पहले कोई सी अपराध किया हो और उसे उस अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो और सजा सुनाई गई हो। इसके बाद, दोषी दूसरा अपराध करता है जिसके लिए उसे दोषी ठहराया जाता है और सजा दिए जाने की आवश्यकता होती है। इससे कोई कानूनी

चुनौती या कठिनाई उत्पन्न नहीं होती. लेकिन, ऐसी स्थिति भी हो सकती है जहां किसी दोषी ने अपराध किया हो और उस अपराध के लिए मुकदमा चल रहा हो। मुकदमे के लंबित रहने के दौरान वह दूसरा अपराध करता है जिसके लिए उसे दोषी ठहराया जाता है और जिसमें सजा दिए जाने की आवश्यकता होती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 54 पिछले बुरे चरित्र के साक्ष्य के उपयोग पर रोक लगाती है, सिवाय इसके कि जब दोषी स्वयं अपने अच्छे चरित्र का साक्ष्य देने का विकल्प चुनता हो। इसका तात्पर्य स्पष्ट रूप से यह है कि निर्दिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर, सजा की मात्रा निर्धारित करने के प्रयोजनों के लिए दोषी के पिछले प्रतिकूल आचरण को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए। [पैरा 58, 59] [617-ए-डी]

3.2 किसी दोषी के खिलाफ केवल एक या अधिक आपराधिक मामलों का लंबित होना सजा सुनाते समय विचार के लिए एक कारक नहीं हो सकता है। न केवल यह वैधानिक रूप से अस्वीकार्य है (कुछ मामलों को छोड़कर) बल्कि अन्यथा यह निर्दोषता की मौलिक धारणा का उल्लंघन करता है - एक मानवाधिकार जिसका हर कोई हकदार है। वर्तमान मामले में अपीलकर्ता के खिलाफ समान अपराधों के लिए दो मामले लंबित हैं। ये दोनों. मुकदमा लंबित था. इसके बावजूद, ट्रायल जज ने इसे अपीलकर्ता के खिलाफ एक परिस्थिति के रूप में ध्यान में रखा। सत्र न्यायाधीश के लिए यह कहीं अधिक उपयुक्त होता प्रतीक्षा की गई, यदि उसने सोचा कि मुकदमे को समाप्त करने के लिए इन मामलों की लंबितता को ध्यान में रखना आवश्यक है। [पैरा 73, 74] [623-बी-डी]

3.3 एक ट्रायल जज अपना समय ले सकता है और अभियोजन पक्ष के साथ-साथ बचाव पक्ष को भी सामग्री पेश करने का पर्याप्त अवसर देने के बाद दोषी को सजा दे सकता है ताकि ट्रायल जज के लिए मौत की सजा के मुकाबले आजीवन कारावास

देने की संभावना खुली रहे। मौत की सजा केवल दुर्लभतम मामलों में ही दी जानी चाहिए, केवल तभी जब कोई वैकल्पिक विकल्प निर्विवाद रूप से बंद हो और सभी कारकों पर पूर्ण विचार करने के बाद ही यह ध्यान में रखा जाए कि मौत की सजा अपरिवर्तनीय है और निष्पादन पर अपरिवर्तनीय है। हालाँकि अपराध महत्वपूर्ण है, जहाँ तक सज़ा देने की प्रक्रिया का सवाल है, अपराधी भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी के ई-कोर्ट प्रोजेक्ट की वेबसाइट को देखने से पता चला कि वास्तव में अपीलकर्ता के खिलाफ वर्तमान मामले सहित कुल चार मामले थे। यह सूचित नहीं किया गया है कि अपीलकर्ता के विरुद्ध पारित दोषसिद्धि आदेश रद्द कर दिए गए हैं या नहीं। [पैरा 75, 77] [623-एफ-एच; 624-सी: 625-बी]

निष्कर्ष

4. जहां तक वर्तमान याचिका का संबंध है, सजा के प्रयोजनों के लिए, सत्र न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के साथ-साथ इस न्यायालय ने अपीलकर्ता के सुधार, पुनर्वास और समाज में सामाजिक पुन: एकीकरण की संभावना पर विचार नहीं किया। वास्तव में, इस संबंध में किसी भी तरह से किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए और इस मामले के तथ्यों के आधार पर किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अदालतों के समक्ष कोई सामग्री या सबूत नहीं रखा गया था। अभियोजन पक्ष ने उपलब्ध डीएनए साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने में लापरवाही बरती और भौतिक साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफलता के कारण अभियोजन पक्ष के खिलाफ और सजा के प्रयोजनों के लिए अपीलकर्ता के पक्ष में प्रतिकूल धारणा बननी चाहिए। सजा सुनाने के प्रयोजनों के लिए, अपीलकर्ता के खिलाफ दो समान मामलों की लंबितता पर विचार करने में भी ट्रायल कोर्ट ने गलती की थी, जिस पर वह कानून के अनुसार विचार नहीं कर सकता था। हालाँकि, अपीलकर्ता के खिलाफ दो (वास्तव में तीन) समान मामलों के संबंध में बाद के घटनाक्रमों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इन सभी कारणों से, इस

पर गौर करना अधिक उचित होगा। अपीलकर्ता द्वारा किए गए अपराध और उसके समग्र व्यक्तित्व और उसके बाद की घटनाओं सहित रिकॉर्ड ए पर मौजूद सामग्री, अपीलकर्ता को दी गई मौत की सजा को कम करने के लिए है, लेकिन यह निर्देशित किया जाता है कि उसे अपने शेष सामान्य जीवन के लिए हिरासत से रिहा नहीं किया जाना चाहिए। [पैरा 79, 80] [625-डी-एच: 626-ए-बी]

बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980) 2 एससीसी 684 का पालन किया गया।

संतोष कुमार सतीश भूषण बरियार बनाम महाराष्ट्र राज्य (2009) 6 एससीसी 498: [2009] 90 एससीआर 90: सुशील शर्मा बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) (2014) 4 एससीसी 317: [2013] 16 एससीआर 616 - पर निर्भर।

शिवाजी उर्फ दद्या शंकर अलहट बनाम महाराष्ट्र राज्य (2008) 15 एससीसी 269: [2008] 13 एससीआर 81: महाराष्ट्र राज्य बनाम शंकर कृष्णराव खाड़े 2008 सभी एमआर (सीआरआई) 2143; शंकर किसनराव खाड़े बनाम महाराष्ट्र राज्य (2013) 5 एससीसी 546 [2013] 6 एससीआर 949: लक्ष्मण नाइक बनाम उड़ीसा राज्य (1994) 3 एससीसी 381: [1994] 2 एससीआर 94; पश्चिम बंगाल राज्य बनाम धनंजय चटर्जी उर्फ धाना। (1994) 2 एससीसी 220: [1994] 1 एससीआर 37: महाराष्ट्र राज्य बनाम भारत फकीरा धीवर (2002) 1 एससीसी 622 [2001] 5 पूरक एससीआर 12: महाराष्ट्र राज्य बनाम सुरेश (2000) 1 एससीसी 471: [1999] 5 पूरक। एससीआर 215; अदु राम बनाम मुकना (2005) 10 एससीसी 597

[2004] 5 पूरक। एससीआर 314: मोलाई और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य। (1999) 9 एससीसी 581: [1999] 4 पूरक। एससीआर 104; राजेंद्र प्रल्हादराव वासनिक बनाम महाराष्ट्र राज्य (2012) 4 एससीसी 37: [2012] 2 एससीआर 225: मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक बनाम रजिस्ट्रार, भारत का सर्वोच्च न्यायालय (2014) 9 एससीसी 737: [2014] 11 एससीआर 1009; बिष्णु प्रसाद सिन्हा बनाम असम राज्य (2007) 11 एससीसी 467 [2007] 1 एससीआर 916: आलोक नाथ दत्ता बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2007) 12 एससीसी 230: [2006] 10 पूरक। एससीआर 662; स्वामी श्रद्धानंद बनाम कर्नाटक राज्य (2007) 12 एससीसी 288 (2007) 7 एससीआर 616; स्वामी श्रद्धानंद (2) बनाम कर्नाटक राज्य (2008) 13 एससीसी 767: (2008) 11 एससीआर 93: सेबस्टियन वाई, केरल राज्य (2010) 1 एससीसी 58: (2010) 1 एससीसी 58; रमेश बनाम राजस्थान राज्य (2011) 3 एससीसी 685: [2011] 4 एससीआर 585; कालू खान बनाम राजस्थान (2015) 16 एससीसी 492; प्रकाश धवल खैरमार (पाटिल) बनाम महाराष्ट्र (2002) 2 एससीसी 35: [2001] 5 पूरक एससीआर 612; लेहना बनाम हरियाणा राज्य (2002) 3 एससीसी 76 : [2002] 1 एससीआर 377; संदेश बनाम महाराष्ट्र राज्य (2013) 2 एससीसी 479: [2012] 13 एससीआर 1049: मोहिंदर सिंह पंजाब राज्य (2013) 3 एससीसी 294 [2013] 3 एससीआर 90: बिरजू बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2014) 3 एससीसी 421: [2014] 1 एससीआर 1047; अनिल बनाम महाराष्ट्र राज्य (2014) 4 एससीसी 69: [2014] 3 एससीआर 34;

महेश धनाजी शिंदे बनाम महाराष्ट्र राज्य (2014) 4 एससीसी 292 [2014] 3 एससीआर 406; छन्नू लाल वर्मा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य सुप्रीम कोर्ट द्वारा 28.11.2018 को आपराधिक अपील संख्या 1482 और 1483 2018 में फैसला: संगीत राज्य हरियाणा (2013) 2 एससीसी 452: गुजरात राज्य बनाम किशनभाई (2014) 5 एससीसी 108 : [2014] 1 एससीआर 197: मुकेश और अंतव। राज्य (एनसीटी दिल्ली) (2017) 6 एससीसी 1: [2017] 6 एससीआर 1; सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य (2010) 7 एससीसी 263 [2010] 5 एससीआर 381; मो. फारूक अब्दुल गफूर बनाम महाराष्ट्र राज्य (2010) 14 एससीसी 641 [2009] 12 एससीआर 1093: गुरमुख सिंह हरियाणा राज्य (2009) 15 एससीसी 635 [2009] 13 एससीआर 548: बंटू बनाम एमपी राज्य (2001) 9 एससीसी 615: [2001] 4 पूरक, एससीआर 298; अमित बनाम महाराष्ट्र राज्य (2003) 8 एससीसी 93: [2003] 2 पूरक। एससीआर 285: राहुल बनाम महाराष्ट्र राज्य (2005) 10 एससीसी 322: सुरेंद्र पाल शिवबालकपाल बनाम गुजरात राज्य (2005) 3 एससीसी 127: [2004] 4 पूरक। एससीआर 464: महामहिम महारानी बनाम नॉर्मन स्कोलनिक [1982] 2 एससीआर 47-संदर्भित।

स्कॉट नाथन श्ल्यूटर बनाम रॉबिन लॉरेंस ट्रेनेरी 1997 6 एनटीएलआर 194 संदर्भित।

कानून मामला संदर्भित

(1980) 2 एससीसी 684	पालन किया	पैरा 2

(2008) 13 एससीआर 81	संदर्भित किया	पैरा 4
(2013) 6 एससीआर 949	संदर्भित किया	पैरा 5
[1994] 2 एससीआर 94	संदर्भित किया	पैरा 8
[1994] 1 एससीआर 37	संदर्भित किया	पैरा 8
[2001] 5 पूरक। एससीआर 12	संदर्भित किया	पैरा 8
[1999] 5 पूरक। एससीआर 215	संदर्भित किया	पैरा 8
[2004] 5 पूरक। एससीआर 314	संदर्भित किया	पैरा 8
[1999] 4 पूरक। एससीआर 104	संदर्भित किया	पैरा 8
[2012] 2 पूरक। एससीआर 225	संदर्भित किया	पैरा 10
[2014] 11 एससीआर 1009	संदर्भित किया	पैरा 12
[2007] 1 एससीआर 916	संदर्भित किया	पैरा 18
[2006] 10 पूरक। एससीआर 662	संदर्भित किया	पैरा 18
[2007] 7 एससीआर 616	संदर्भित किया	पैरा 20
[2008] 11 एससीआर 93	संदर्भित किया	पैरा 22
[2009] 9 एससीआर 90	संदर्भित किया	पैरा 24
[2010] 1 एससीसी 58	संदर्भित किया	पैरा 25
[2011] 4 एससीसी 585	संदर्भित किया	पैरा 26

[2013] 16 एससीसी 616	संदर्भित किया	पैरा 27
[2015] 16 एससीसी 492	संदर्भित किया	पैरा 28
[2001] 5 पूरक एससीआर 612	संदर्भित किया	पैरा 33
[2002] 1 एससीआर 377	संदर्भित किया	पैरा 34
[2012] 13 एससीआर 1049	संदर्भित किया	पैरा 37
[2013] 3 एससीआर 90	संदर्भित किया	पैरा 38
[2014] 1 एससीआर 1047	संदर्भित किया	पैरा 39
[2014] 3 एससीसी 34	संदर्भित किया	पैरा 40
[2014] 3 एससीसी 406	संदर्भित किया	पैरा 41
[2013] 2 एससीसी 452	संदर्भित किया	पैरा 47
[2014] 1 एससीसी 197	संदर्भित किया	पैरा 52
[2017] 6 एससीसी 1	संदर्भित किया	पैरा 53
[2010] 5 एससीआर 381	संदर्भित किया	पैरा 56
[2009] 12 एससीआर 1093	संदर्भित किया	पैरा 65
[2009] 13 एससीसी 548	संदर्भित किया	पैरा 66
[2001] 4 पूरक एससीआर 298	संदर्भित किया	पैरा 67
[2003] 3 पूरक एससीआर 285	संदर्भित किया	पैरा 68

[2005] 10 एससीसी 322	संदर्भित किया	पैरा 70
[2004] 4 पूरक एससीआर 464	संदर्भित किया	पैरा 70
[1992] 2 एससीआर 47	संदर्भित किया	पैरा 71

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार: समीक्षा पिटीशन (आपराधिक) संख्या 306-307/2013

में

आपराधिक अपील संख्या 145-146/2011

बॉम्बे में न्यायिक उच्च न्यायालय, नागपुर में नागपुर खंडपीठ के 2008 की आपराधिक अपील संख्या 700 के साथ 2008 के आपराधिक पुष्टिकरण मामले संख्या 3 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 26.03.2009 से।

युग मोहित चौधरी, सिद्धार्थ, पयोशी, एस. प्रभु रामसुब्रमण्यम, पांडियाराजन, विलियम विनोथकुमार, एस गौतमन अधिवक्ता, अपीलकर्ता के लिए।

निशांत रमाकांतराव कटनेश्वरकर, सुश्री दीपा कुलकर्णी, अनूप कंडारी, अधिवक्ता प्रतिवादी के लिए।

न्यायालय का निर्णय मदन बी. लोकुर, जे. द्वारा सुनाया गया।

1. "मौत की सजा' - इन कुछ शब्दों का किसी भी व्यक्ति पर, यहां तक कि एक कठोर अपराधी पर भी, रोंगटे खड़े कर देने वाला प्रभाव पड़ेगा। हमारा समाज इसके निवारक प्रभाव के आधार पर ऐसी सजा की मांग करता है, हालांकि इसके निवारक प्रभाव पर कोई निर्णायक अध्ययन नहीं है। हमारा समाज भी एक भयानक अपराध किए जाने के प्रतिशोध के रूप में मौत की सजा की मांग की जाती है। सजा हालांकि

फिर भी कोई निर्णायक अध्ययन नहीं है कि क्या प्रतिशोध अपने आप में समाज को संतुष्ट करता है। दूसरी ओर, ऐसे विचार हैं जो सुझाव देते हैं कि किसी अपराध के लिए सजा को और अधिक ध्यान से देखा जाना चाहिए मानवीय दृष्टिकोण और किसी व्यक्ति को जघन्य अपराध करने के लिए प्रेरित करने के कारणों का पता लगाया जाना चाहिए। एक विचार यह भी है कि यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि क्या प्रतिनिधित्व करने वालों के साथ-साथ एक कठोर अपराधी को भी सुधारना, पुनर्वास करना और समाज में सामाजिक रूप अपराध के शिकार पुनः स्थापित करना संभव है।

2. ये परस्पर विरोधी विचार अदालतों के लिए निर्णय लेना बहुत कठिन बना देते हैं और विषय पर विशेषज्ञ साक्ष्य के बिना, अदालतें वस्तुनिष्ठ राय बनाने में सक्षम नहीं होती हैं। लेकिन, बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980) 2 एससीसी 684 मामले में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने मानवीय दृष्टिकोण पर अपना जोर दिया है और अपराधी के सुधार या पुनर्वास की संभावना पर विचार करना अनिवार्य कर दिया है और अभियोजन पक्ष को यह साबित करने की आवश्यकता है कि यह संभव नहीं है। दोषी व्यक्ति का सुधार या पुनर्वास किया जाना। हालाँकि, संविधान पीठ ने एक गलियारा खुला छोड़ दिया अनिश्चितता के कारण, दुर्लभ से दुर्लभ मामलों में, मौत की सज़ा की घोषणा की जा सकती है। यह वह प्रतिमान है जो इन याचिकाओं में हमारा सामना करता है।

पृष्ठभूमि

3. अपीलकर्ता को 3 वर्ष की लड़की के बलात्कार और हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है। अपराध 2 और 3 मार्च, 2007 की मध्यरात्रि को किया गया था। अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर, अपीलकर्ता को धारा 376 (2) (1), 377 और के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी पाया गया और दोषी

ठहराया गया। सत्र न्यायाधीश, अमरावती द्वारा 2007 के सत्र परीक्षण संख्या 183 में 6 सितंबर, 2008 के एक निर्णय द्वारा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302।

4. दी जाने वाली सज़ा के संबंध में, ट्रायल जज ने अभियोजन और अपीलकर्ता को 6 सितंबर, 2008 को और फिर 8 सितंबर, 2008 को सुना, जिस दिन उन्होंने प्रारंभिक आदेश पारित किया। उस तारीख को लोक अभियोजक के साथ-साथ बचाव पक्ष के विद्वान वकील की दलीलें सुनी गईं और शिवाजी उर्फ दद्या शंकर अलहट बनाम महाराष्ट्र राज्य (2008) 15 एससीसी 269 में इस न्यायालय के फैसले का संदर्भ दिया गया। इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में रिपोर्ट के पैराग्राफ 27 में यह देखा गया:

> "27. यह दलील कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में मौत की सज़ा नहीं दी जानी चाहिए, बिना किसी तर्क के है। यदि परिस्थितिजन्य साक्ष्य आरोपी के अपराध को स्थापित करने में निर्विवाद चरित्र के पाए जाते हैं, तो यह दोषसिद्धि का आधार बनता है। इसमें कुछ भी नहीं है सजा के सवाल से संबंधित, जैसा कि इस न्यायालय ने विभिन्न मामलों में मौत की सजा देते समय देखा है। कम करने वाली परिस्थितियों और गंभीर परिस्थितियों को संतुलित करना होगा। ऐसी परिस्थितियों की बैलेंस शीट में, तथ्य यह है कि मामला परिस्थितिजन्य पर निर्भर करता है सबूतों की कोई भूमिका नहीं होती है। वास्तव में अधिकांश मामलों में जहां बलात्कार और हत्या आदि के लिए मौत की सजा दी जाती है, व्यावहारिक रूप से प्रत्यक्षदर्शी होने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। वे सार्वजनिक दृष्टिकोण से प्रतिबद्ध नहीं होते हैं। लेकिन प्रकृति ही यही है ऐसे मामलों में, उपलब्ध साक्ष्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य है। यदि उक्त साक्ष्य को दोषसिद्धि दर्ज करने के उद्देश्य से विश्वसनीय, ठोस और भरोसेमंद

पाया गया है, तो उस साक्ष्य को एक कम करने वाली परिस्थिति के रूप में मानना, एक अप्रासंगिक पहलू विद्वान की दलील पर विचार करना होगा। एमिकस क्यूरी का कहना है कि दोषसिद्धि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है और इसलिए, मौत की सजा नहीं दी जानी चाहिए, यह स्पष्ट रूप से टिकाऊ नहीं है।" (जोर हमारे द्वारा दिया गया है)।

इसके बाद, विद्वान सत्र न्यायाधीश ने 10 सितंबर 2008 को एक आदेश पारित कर अपीलकर्ता को मौत की सजा सुनाई।

5. हमने 8 सितंबर, 2008 के साथ-साथ 10 सितंबर, 2008 को पारित आदेशों का अध्ययन किया है और पाया है कि सत्र न्यायाधीश ने मुख्य रूप से अपराध की प्रकृति और गंभीरता और अपीलकर्ता के कुछ व्यक्तिगत कारकों जैसे तथ्य पर चर्चा की है। उनका एक बच्चा है जिसकी उम्र 9 साल है और उसके माता-पिता उस पर निर्भर हैं। सत्र न्यायाधीश ने इस तथ्य पर भी विचार किया कि अपीलकर्ता के खिलाफ कानून के समान प्रावधानों के तहत दो अन्य मामले लंबित हैं और उन्होंने राय व्यक्त की कि उन मामलों की लंबितता अपीलकर्ता के खिलाफ एक परिस्थिति है। इसके लिए, महाराष्ट्र राज्य बनाम शंकर कृष्णराव खाड़े 2008 ऑल एमआर (आपराधिक) 2143 पर भरोसा रखा गया था। यह उल्लेख किया जा सकता है कि शंकर में बॉम्बे उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को इस न्यायालय ने शंकर किसनराव खाड़े बनाम महाराष्ट्र राज्य के पैराग्राफ में स्वीकार नहीं किया था। रिपोर्ट के 60 और 61। (2013) 5 एससीसी 546।

6. मामले की परिस्थितियों के समग्र दृष्टिकोण पर, सत्र न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला कि सजा का कोई भी वैकल्पिक विकल्प निर्विवाद रूप से बंद है और इसलिए अपीलकर्ता को दी जाने वाली एकमात्र सजा मृत्युदंड है।

7. अपीलकर्ता ने 2008 की आपराधिक अपील संख्या 700 के तहत बंबई उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ अपील की। इसे 2008 की आपराधिक पुष्टिकरण मामले संख्या 3 के साथ सुना गया था। इन दोनों को विचार और सजा के लिए लिया गया था। को बरकरार रखा गया और अपीलकर्ता को दी गई मृत्युदंड की पुष्टि उच्च न्यायालय ने 26 मार्च, 2009 के एक फैसले और आदेश द्वारा की।

8. उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता को दी जाने वाली सजा के प्रश्न पर विचार किया। (हम दोषसिद्धि के गुण-दोष से चिंतित नहीं हैं)। फैसले को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने अपीलकर्ता को दी गई सजा के सवाल पर बॉम्बे हाई कोर्ट में बहस की और मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने के लिए की गई प्राथमिक दलील यह थी कि यह मामला परिस्थितिजन्य था। प्रमाण का सन्दर्भ दिया गया। लक्ष्मण नाइक बनाम उड़ीसा राज्य', (1994) 3 एससीसी 381, धनंजय चटर्जी उर्फ धाना बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (1994) 2 एससीसी 220, महाराष्ट्र राज्य बनाम भारत फकीरा धीवर (2002) 1 एससीसी 622, महाराष्ट्र राज्य बनाम सुरेश', (2000) 1 एससीसी 471, अदु राम बनाम मुकना, (2005) 10 एससीसी 597, और मोलाई और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, "एआईआर 2000 एससी 177 - (1999) 9 एससीसी 581।

9. इसके बाद, उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया -'

> "हमने उपरोक्त न्यायिक उदाहरणों के आलोक में वर्तमान मामले के तथ्यों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और पाया है कि विद्वान ट्रायल जज ने सही फैसला दिया कि अपीलकर्ता मृत्युदंड का हकदार था। अपीलकर्ता का आचरण मानवीय मूल्यों के प्रति पूर्ण उपेक्षा

दर्शाता है और पूरी तरह से भ्रष्ट, क्रूर दर्शाता है। और एक षडयंत्रकारी दिमाग ने एक असहाय बच्चे का फायदा उठाया, इस बात की कोई चिंता नहीं दिखाई कि उसकी वासना ने बच्चे में जीवन की लौ को बुझा दिया। इसलिए, हम दंड संहिता की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलकर्ता पर लगाई गई मौत की सजा की पुष्टि करते हैं। हम दोषी की अपील को भी खारिज करें और उसकी दोषसिद्धि के साथ-साथ लगाई गई सजा को भी बरकरार रखें।" (जोर हमारे द्वारा दिया गया)।

10. उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से व्यथित महसूस करते हुए, अपीलकर्ता ने इस न्यायालय में 2011 की आपराधिक अपील संख्या 145-146 के तहत अपील की। इन अपीलों को 29 फरवरी, 2012 के एक निर्णय और आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। (राजेंद्र प्रल्हाद्र वासनिक बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2012)-4-एससीसी 37)

11. अपीलकर्ता द्वारा 2012 की आर.पी. (सी) डायरी संख्या 26107 के तहत समीक्षा याचिकाएं दायर की गईं, जिन्हें 7 मार्च, 2013 के एक आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया।

12. इसके बाद, एक पूरी तरह से अलग मामले में, मोहम्मद में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ। आरिफ उर्फ अशफाक बनाम रजिस्ट्रार, भारत के सर्वोच्च न्यायालय (2014)9 एससीसी 737) ने उन मामलों में दो बुनियादी मुद्दों पर विचार किया जहां उच्च न्यायालय द्वारा मौत की सजा सुनाई गई थी। ये दो मुद्दे थे: (1) क्या उन मामलों की सुनवाई जिनमें मौत की सजा दी गई है, इस न्यायालय के पांच नहीं तो कम से कम तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की जानी चाहिए, और (2) क्या मौत

की सजा में समीक्षा याचिकाओं की सुनवाई होनी चाहिए मामले प्रचलन से नहीं, बल्कि खुली अदालत में ही होने चाहिए।

13. इन मुद्दों पर विचार करते हुए, संविधान पीठ ने माना कि अब से इस न्यायालय में लंबित प्रत्येक अपील जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा मौत की सजा दी गई है, केवल तीन न्यायाधीशों की पीठ ही अपील सुनेगी। संविधान पीठ को इस दलील को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं किया गया कि अपील की सुनवाई पांच न्यायाधीशों द्वारा की जानी चाहिए। खुली अदालत में मौखिक सुनवाई के संबंध में, यह माना गया कि जिन मामलों में मौत की सजा दी गई है, उनमें सीमित मौखिक सुनवाई दी जानी चाहिए और यह लंबित समीक्षा याचिकाओं और भविष्य में दायर ऐसी समीक्षा याचिकाओं पर लागू होगी। यह निर्देश वहां भी लागू होगा जहां समीक्षा याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है लेकिन मौत की सजा पर अमल नहीं हुआ है। ऐसे मामलों में दोषी संविधान पीठ द्वारा दिए गए फैसले की तारीख से एक महीने के भीतर समीक्षा याचिका को फिर से खोलने के लिए आवेदन कर सकता है। हालाँकि, जिन मामलों में सुधारात्मक याचिका भी खारिज हो जाती है, ऐसे मामलों को फिर से खोलना उचित नहीं होगा।

14. वर्तमान अपील में, अपीलकर्ता द्वारा कोई उपचारात्मक याचिका दायर नहीं की गई थी और इसलिए संविधान पीठ के फैसले के मद्देनजर, 24 मार्च, 2015 के एक आदेश द्वारा समीक्षा याचिकाएं बहाल कर दी गईं और इस तरह वे सामने आईं। साढ़े तीन वर्ष से अधिक के अंतराल के बाद हमारे समक्ष विचार हेतु।

प्रविष्टियों:-

15. अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि बचन सिंह मामले में इस न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, कई

प्रकार के कारक हैं जिन्हें मौत की सजा देते समय ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। इसके बावजूद, विद्वान वकील ने हमारे सामने केवल मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने के सवाल पर खुद को चार प्रमुख तर्कों तक ही सीमित रखा। जिन चार एफ तर्कों का आग्रह किया गया वे थे।

1. दोषसिद्धि परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित थी और ऐसे मामलों में, आमतौर पर मौत की सज़ा नहीं दी जानी चाहिए।

2. इस तरह के विचार को अनिवार्य करने वाले कई निर्णयों के बावजूद अपीलकर्ता के सुधार और पुनर्वास की संभावना पर न तो ट्रायल कोर्ट द्वारा, न ही उच्च न्यायालय द्वारा या यहां तक कि इस न्यायालय द्वारा भी विचार नहीं किया गया। यह प्रस्तुत किया गया कि ऐसी संभावना है कि अपीलकर्ता को सुधारा और पुनर्वासित किया जा सकता है।

3. महत्वपूर्ण डीएनए साक्ष्य को ट्रायल कोर्ट के समक्ष नहीं रखा गया या आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 53-ए (संक्षेप में 'सीआरपीसी) और सीआरपीसी की धारा 164-ए के प्रावधानों के विपरीत विचार नहीं किया गया।"

"धारा 53 ए. बलात्कार के आरोपी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा जांच-

(1) जब किसी व्यक्ति को बलात्कार का अपराध करने या बलात्कार करने का प्रयास करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि उसके व्यक्ति की जांच करने से साक्ष्य मिल सकेगा। इस तरह के अपराध को अंजाम देना सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा संचालित अस्पताल में कार्यरत एक

पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के लिए वैध होगा और उस स्थान से सोलह किलोमीटर के दायरे में ऐसे चिकित्सक की अनुपस्थिति में जहां अपराध हुआ है किसी अन्य पंजीकृत चिकित्सक द्वारा उप-निरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी के अनुरोध पर, और उसकी सहायता में और उसके निर्देशन में सद्भावनापूर्वक कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए, गिरफ्तार की ऐसी जांच करने के लिए प्रतिबद्ध है। व्यक्ति और ऐसे बल का प्रयोग करना जो उस उद्देश्य के लिए उचित रूप से आवश्यक हो।

(2) ऐसी परीक्षा आयोजित करने वाला पंजीकृत चिकित्सक बिना किसी देरी के ऐसे व्यक्ति की जांच करेगा और उसकी जांच की एक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित विवरण दिए जाएंगे, अर्थात्

(i) आरोपी का नाम और पता और उस व्यक्ति का जिसके द्वारा उसे लाया गया था,

(ii) आरोपी की उम्र।

(iii) अभियुक्त के शरीर पर इन्जरी के निशान, यदि कोई हों।

(iv) डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए आरोपी के व्यक्ति से ली गई सामग्री का विवरण और

(v) उचित विवरण में अन्य सामग्री विवरण।

(3) रिपोर्ट में प्रत्येक निर्णय के सटीक कारण बताये जायेंगे
(4) परीक्षा शुरू होने और पूरा होने का सही समय भी रिपोर्ट में नोट किया जाएगा।

(5) पंजीकृत चिकित्सक, बिना देरी किए, रिपोर्ट को अग्रेषित करेगा। जांच अधिकारी, जो इसे धारा 173 में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करेगा
उस धारा की उपधारा (5) के खंड (ए) में निर्दिष्ट दस्तावेजों का हिस्सा
164 ए. बलात्कार की शिकार पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण.- (1) जहां, अवस्था के

दौरान जब बलात्कार करने या बलात्कार करने का प्रयास करने के अपराध की जांच चल रही हो जिस महिला के साथ बलात्कार का आरोप लगाया गया है या प्रयास किया गया है, उसका व्यक्तित्व प्राप्त करने का प्रस्ताव है ऐसा परीक्षण किया गया हो या प्रयास किया गया हो, किसी चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा जांच की गई हो द्वारा संचालित अस्पताल में कार्यरत पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा संचालित किया जाएगा सरकार या स्थानीय प्राधिकारी और ऐसे किसी व्यवसायी की अनुपस्थिति में, किसी के द्वारा अन्य पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी, ऐसी महिला या किसी व्यक्ति की सहमति से अपनी ओर से ऐसी सहमति देने में सक्षम है और ऐसी महिला को ऐसे ही भेजा जाएगा प्राप्त होने के चौबीस घंटे के भीतर पंजीकृत चिकित्सक सामाजिक अपराध के घटित होने से संबंधित जानकारी

(2) पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी, जिसके पास ऐसी महिला भेजी जाती है, बिना देरी से उसके व्यक्ति की जांच करता है और निम्नलिखित देते हुए उसकी परीक्षा की एक रिपोर्ट तैयार करता है विवरण, अर्थात्

(i) महिला और उस व्यक्ति का नाम और पता जिसके द्वारा उसे लाया गया था।

(ii) महिला की उम्र;

(iii) डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए महिला के शरीर से ली गई सामग्री का विवरण;

4. अपीलकर्ता के पिछले इतिहास के संदर्भ की आवश्यकता नहीं थी।

हम प्रस्तुतियों को क्रमानुसार निपटाने का प्रस्ताव करते हैं।

परिस्थितिजन्य साक्ष्य

16. उच्च न्यायालय द्वारा संदर्भित लक्ष्मण नाइक, धनंजय चटर्जी और मोलाई के मामलों में, किसी भी तरह से इस बात पर कोई चर्चा नहीं है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषी ठहराए जाने पर मृत्युदंड दिया जाना चाहिए या नहीं। जिस बात पर चर्चा की गई वह अपराध की क्रूरता थी जिसके कारण मृत्युदंड देना आवश्यक हो गया। ये निर्णय अपीलकर्ता के मामले को आगे नहीं बढ़ाते हैं।

17. अब हम परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर मौत की सजा देने के पक्षकारों के विद्वान वकील द्वारा हमारे समक्ष उद्धृत मामलों पर विचार करते हैं।

18. बिष्णु प्रसाद सिन्हा बनाम असम राज्य ((2007) 11 एससीसी 467) में इस न्यायालय ने रिपोर्ट के पैराग्राफ 55 में इस प्रस्ताव को प्रभावी ढंग से स्वीकार कर लिया कि यदि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के साथ-साथ कुछ अन्य लाभकारी कारकों से संबंध साबित हो जाता है तो आम तौर पर दोषी को मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। इसे इस प्रकार आयोजित किया गया:

> "55. प्रश्न यह है कि क्या सज़ा दी जानी चाहिए। आमतौर पर, यह न्यायालय, अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, इस संबंध में विद्वान सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की राय से असहमत नहीं होता, लेकिन ऐसा होना ही चाहिए।

(iv) महिला के शरीर पर चोट के निशान, यदि कोई हों

(v)महिला की सामान्य मानसिक स्थिति, और

(vi) उचित विवरण सहित अन्य सामग्री विवरण

(3) रिपोर्ट में प्रत्येक निष्कर्ष के सटीक कारण बताए जाएंगे।

4) रिपोर्ट में विशेष रूप से दर्ज किया जाएगा कि ऐसी परीक्षा के लिए महिला या उसकी ओर से सहमति देने के लिए सक्षम व्यक्ति की सहमति प्राप्त की गई थी।

(5) रिपोर्ट में परीक्षा शुरू होने और खत्म होने का सही समय भी नोट किया जाएगा।

(6) पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी बिना किसी देरी के रिपोर्ट को जांच अधिकारी को अग्रेषित करेगा वह अनुभाग जो इसे उप-धारा (5) के खंड (ए) में निर्दिष्ट दस्तावेजों के हिस्से के रूप में धारा 173 में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करेगा।

(7) इस धारा में किसी भी बात को महिला या ऐसी सहमति देने के लिए सक्षम किसी व्यक्ति की सहमति के बिना किसी भी परीक्षा को वैध बनाने के रूप में उसकी ओर से स्पष्टीकरण नहीं माना जाएगा।। इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए, "परीक्षा" और "पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के वही अर्थ होंगे जो धारा 53 में हैं।

> यह ध्यान में रखें कि अपीलकर्ताओं को केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषी ठहराया जाता है। इस प्रस्ताव के लिए प्राधिकारी हैं कि यदि साक्ष्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य से साबित हो जाता है, तो आम तौर पर मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा, अपीलकर्ता 1 ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपने बयान में भी पश्चाताप और पश्चाताप दिखाया। उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया।" (हमारे द्वारा जोर दिया गया)।

19. आलोक नाथ दत्ता बनाम पश्चिम बंगाल राज्य ((2007) 12 एससीसी 230) में यह सिद्धांत कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य से उत्पन्न मामले में आम तौर पर मौत की सजा नहीं दी जानी चाहिए, इस शर्त के साथ व्यापक रूप से स्वीकार किया गया था कि

मौत की सजा देने के लिए कुछ "विशेष कारण" होना चाहिए। दंड। इसे रिपोर्ट के पैराग्राफ 174 में इस प्रकार रखा गया था:

> "174. इस न्यायालय के कुछ उदाहरण हैं जैसे सहदेव बनाम यूपी राज्य। (2004) 10 एससीसी 682] और एस.के इशाक बनाम बिहार राज्य [(1995) 3 एससीसी 392] जो इस प्रस्ताव के लिए प्राधिकारी हैं कि यदि अपराध परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से साबित होता है, आमतौर पर मौत की सजा नहीं दी जानी चाहिए। हमारा मानना है कि हमें इसके बजाय उक्त उदाहरणों का पालन करना चाहिए और इस प्रकार, मौत की सजा देने के बजाय, आलोक नाथ के खिलाफ आजीवन कारावास की सजा देनी चाहिए। इसके अलावा हम मृत्युदंड देने का कोई विशेष कारण नहीं मिला जो कि अनिवार्य है।" (जोर हमारे द्वारा दिया गया)।

20. स्वामी श्रद्धानंद बनाम कर्नाटक राज्य ((2007) 12 एससीसी 288) में इस न्यायालय ने रिपोर्ट के पैराग्राफ 87 में सावधानी बरतने की बात कही कि प्रतीत होने वाले निर्णायक परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर दोषसिद्धि को मूर्खतापूर्ण नहीं माना जाना चाहिए। ये हुआ था:

> "87. मृत्युदंड न्यायशास्त्र के क्षेत्र में कई अध्ययनों में यह एक बुनियादी बिंदु रहा है कि जिन मामलों में दोषसिद्धि का एकमात्र आधार परिस्थितिजन्य साक्ष्य है, उनमें बाद में गलत दोषसिद्धि होने की संभावना उन मामलों की तुलना में कहीं अधिक होती है। जो सबूत के बेहतर स्रोतों पर आधारित हैं। प्रतीत होता है कि निर्णायक परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि को मूर्खतापूर्ण घटनाओं

के रूप में नहीं माना जाना चाहिए और यह तथ्य कि ये परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हैं, सजा के चरण के विचार-विमर्श में एक निश्चित कारक होना चाहिए, उस पूंजी पर विचार करते हुए सज़ा अपनी पूर्ण अपरिवर्तनीयता में अद्वितीय है। मुकदमे की कोई भी विशेषता, जैसे कि केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित सजा, जो दोषी गणना में अनिश्चितता में योगदान करती है, हत्या के लिए अधिकतम दंड तय करते समय नकारात्मक ध्यान आकर्षित करना चाहिए।" (हमारे द्वारा जोर दिया गया)।

21. स्वामी श्रद्धानंद में न्यायमूर्ति एस.बी. सिन्हा द्वारा लिया गया।दृष्टिकोण पर कहना था कि मामले के तथ्यों के आधार पर, मौत की सजा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपीलकर्ता को आजीवन कारावास की सजा दी जानी चाहिए, जिसका अर्थ जीवन भर की सजा के रूप में होना चाहिए। हालाँकि, न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू ने दी जाने वाली सजा पर मतभेद व्यक्त किया और विचार व्यक्त किया कि यह मामला ऐसा था जहाँ हत्या नृशंस, गणनात्मक और शैतानी थी। विद्वान न्यायाधीश की राय थी कि यह मामला दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में आता है। और यदि मृत्युदंड की पुष्टि नहीं की गई तो यह न्याय का मखौल होगा। तदनुसार, विद्वान न्यायाधीश ने मृत्युदंड की पुष्टि की।

22. सज़ा की मात्रा के संबंध में मतभेद को देखते हुए, मामला तीन विद्वान न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ को भेजा गया। बड़ी पीठ के फैसले को स्वामी श्रद्धानंद (2) बनाम कर्नाटक राज्य (2008) 13 एससीसी 767) के रूप में बताया गया है।"

23. बड़ी पीठ ने यह विचार किया कि मामला केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्यों में से एक था। हालाँकि, मामले के संपूर्ण तथ्यों पर विचार करते हुए, खंडपीठ ने आजीवन कारावास (जो आम तौर पर 14 वर्ष है) और मृत्यु के बीच कारावास के अंतर को ध्यान

में रखते हुए सजा की मात्रा पर अपनी राय व्यक्त की। इस पर विचार करते समय, यह माना गया कि अंतर को देखते हुए, न्यायालय को मृत्युदंड का समर्थन करने का प्रलोभन दिया जा सकता है, लेकिन विकल्पों का विस्तार करने और अंतर को पाटने के लिए यह कहीं अधिक न्यायसंगत, उचित और उचित कार्रवाई होगी। यह बचन सिंह मामले में संविधान पीठ के फैसले पर दोबारा जोर देने के साथ-साथ दंडशास्त्र की आधुनिक प्रवृत्तियों के अनुरूप भी होगा। नतीजतन, सर्वसम्मति से मौत की सजा को आजीवन कारावास से बदल दिया गया, इस निर्देश के साथ कि दोषी को उसके शेष जीवन के लिए या आदेश में निर्दिष्ट वास्तविक अवधि के लिए जेल से रिहा नहीं किया जाना चाहिए, जैसा भी मामला हो। यह विचार न्यायमूर्ति एस.बी. द्वारा व्यक्त किया गया। सिन्हा का समर्थन किया गया और यह निर्देश दिया गया कि दोषी को जीवन भर जेल से रिहा नहीं किया जाएगा। रिपोर्ट के पैराग्राफ 92 से 95 में इस न्यायालय द्वारा व्यक्त विचार नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

> "92. मामले को थोड़ा अलग नजरिए से देखा जा सकता है। सजा के मुद्दे के दो पहलू हैं। एक सजा अत्यधिक और अनुचित रूप से कठोर हो सकती है या यह अत्यधिक असंगत रूप से अपर्याप्त हो सकती है। जब कोई अपीलकर्ता इस अदालत में दी गई मौत की सजा लेकर आता है ट्रायल कोर्ट द्वारा और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए जाने के बाद, यह न्यायालय, वर्तमान अपील की तरह, यह पा सकता है कि मामला दुर्लभतम की श्रेणी में नहीं आता है और मौत की सजा का समर्थन करने में कुछ हद तक अनिच्छुक महसूस कर सकता है। लेकिन साथ ही समय के साथ, अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय दृढ़ता से महसूस कर सकता है कि आजीवन कारावास की सज़ा जिसमें छूट के अधीन सामान्यतः 14 वर्ष की अवधि होती है,

अत्यधिक अनुपातहीन और अपर्याप्त होगी। तो फिर न्यायालय को क्या करना चाहिए? यदि न्यायालय का विकल्प केवल दो दंडों तक ही सीमित है, एक कारावास की सजा, सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए, 14 वर्ष से अधिक नहीं और दूसरी मृत्यु, न्यायालय प्रलोभित महसूस कर सकता है और खुद को मृत्युदंड का समर्थन करने के लिए प्रेरित कर सकता है। ऐसा पाठ्यक्रम वास्तव में विनाशकारी होगा। कहीं अधिक न्यायसंगत, उचित और उचित कदम यह होगा कि विकल्पों का विस्तार किया जाए और जो वस्तुतः कानूनी रूप से न्यायालय के अधीन है, उसे अपने अधिकार में ले लिया जाए, यानी 14 साल की कैद और मौत के बीच का बड़ा अंतराल। इस बात पर जोर देने की जरूरत है कि न्यायालय मुख्य रूप से विस्तारित विकल्प का सहारा लेगा क्योंकि मामले के तथ्यों के अनुसार, 14 साल की कैद की सजा बिल्कुल भी सजा नहीं होगी।

93. इसके अलावा, सजा की एक विशेष श्रेणी की औपचारिकता, हालांकि बहुत कम मामलों के लिए, क़ानून की किताब में मृत्युदंड होने का बड़ा फायदा होगा लेकिन वास्तव में इसे जितना संभव हो उतना कम उपयोग करना होगा, वास्तव में दुर्लभतम में तारे के मामले. यह केवल बचन सिंह [(1980) 2 एससीसी 684] मामले में संविधान पीठ के फैसले का पुनर्मूल्यांकन होगा, इसके अलावा यह दंडशास्त्र में आधुनिक रुझानों के अनुरूप भी होगा।

94. ऊपर की गई चर्चाओं के आलोक में हमारा स्पष्ट मानना है कि न्यायालय के पास मृत्युदंड के स्थान पर आजीवन कारावास या चौदह

वर्ष से अधिक की अवधि की सजा देने का एक अच्छा और मजबूत आधार है और आगे यह निर्देश देना है कि दोषी को उसके शेष जीवन के लिए या आदेश में निर्दिष्ट वास्तविक अवधि के लिए जेल से रिहा नहीं किया जाना चाहिए, जैसा भी मामला हो।

95. अंत में, हम सिन्हा, जे द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से सहमत हैं। हम तदनुसार अपीलकर्ता को ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई मौत की सजा को प्रतिस्थापित करते हैं और उच्च न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की पुष्टि करते हैं और निर्देश देते हैं कि उसे जेल से रिहा नहीं किया जाएगा। उसके शेष जीवन तक. (हमारे द्वारा दिया गया जोर)।"

24. संतोष कुमार सतीश भूषण बरियार बनाम महाराष्ट्र राज्य (2009) 6 एससीसी 498 में इस न्यायालय ने रिपोर्ट के पैराग्राफ 167 में स्पष्ट रूप से इस आशय का कानून निर्धारित किया है कि हालांकि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में मौत की सजा देने पर कानून में कोई रोक नहीं है, लेकिन वह साक्ष्य को एक असाधारण मामले की ओर ले जाना चाहिए। यह कहा गया था:

"167. पूरा अभियोजन मामला अनुमोदक के साक्ष्य पर निर्भर करता है। मौत की सजा देने के उद्देश्य से, उस कारक को ध्यान में रखना होगा। हम मान लेंगे कि स्वामी श्रद्धानंद (2) में, इस न्यायालय ने यह निर्धारित नहीं किया था एक दृढ़ कानून है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य से जुड़े मामले में मृत्युदंड देने की अनुमति नहीं होगी। लेकिन, इसके संबंध में भी जो सवाल उठेगा वह यह होगा कि क्या किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कुछ अनुमान, कुछ परिकल्पना आवश्यक होगी जिस तरीके से अपराध किया गया था वह उस मामले से भिन्न

है जहां घटना के तरीके की कोई भूमिका नहीं थी। यहां तक कि जहां मौत की सजा परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दी जानी है, परिस्थितिजन्य साक्ष्य ऐसे होने चाहिए जो परिणाम की ओर ले जाएं। एक असाधारण मामला।" (जोर हमारे द्वारा दिया गया)।

25. सेबस्टियन बनाम केरल राज्य (2010) 1 एससीसी 58 में रिपोर्ट के पैराग्राफ 17 और 18 में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में मृत्युदंड का एक संक्षिप्त संदर्भ है। मौत की सज़ा को आजीवन कारावास में बदलते समय, इस न्यायालय ने स्वामी श्रद्धानंद (2) पर भरोसा किया और कहा:

"17. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने अंततः आग्रह किया कि इन परिस्थितियों में मौत की सजा की मांग नहीं की गई थी। उन्होंने बताया कि मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है और ऐसे मामले में आम तौर पर मौत की सजा नहीं दी जानी चाहिए। इस बात पर भी जोर दिया गया है कि घटना के समय अपीलकर्ता 24 वर्ष का युवक था।

18. हमारी राय है कि इन तथ्यों की पृष्ठभूमि में, मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया जाना चाहिए, लेकिन स्वामी श्रद्धानंद (2) बनाम कर्नाटक राज्य ((2008) 13) में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार एससीसी 767) क्योंकि एक व्यवस्थित समाज के सदस्य के रूप में उनका बने रहना अनावश्यक है (जोर हमारे द्वारा दिया गया है)

26. रमेश बनाम राजस्थान राज्य (2011) 3 एससीसी 685 में इस न्यायालय ने बरियार का उल्लेख किया और रिपोर्ट के पैराग्राफ 68 और पैराग्राफ 69 में, यह अभिनिर्धारित किया गया

> "68. इस प्रकार, न्यायालय ने एक निर्देशित तरीके से साक्ष्य की गुणवत्ता का उल्लेख किया है और चेतावनी दी है कि ऐसे मामले में जहां निर्भरता परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर है, मौत का फैसला देते समय उस कारक को ध्यान में रखा जाना चाहिए वाक्य। यह भी पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामला है। हमें यह नहीं समझा जाना चाहिए कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के सभी मामलों में मौत की सजा नहीं दी जा सकती।
>
> 69. वास्तव में शिवाजी बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में इस न्यायालय ने मौत की सजा सुनाई थी, हालांकि सबूत परिस्थितिजन्य प्रकृति के थे। हम बस इतना ही कहते हैं कि मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर होना प्रासंगिक विचारों में से एक है। हमने सजा नीति तैयार करने में इसे केवल एक परिस्थिति के रूप में नोट किया है....." (हमारे द्वारा जोर दिया गया)

27. सुशील शर्मा बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) (2014) 4 एससीसी 317 में इस न्यायालय ने मामले के विशिष्ट तथ्यों पर विचार किया और मृत्युदंड नहीं दिया क्योंकि एकमात्र साक्ष्य परिस्थितिजन्य था और कुछ कारक थे जो अपीलकर्ता के लाभ के लिए थे। इसे रिपोर्ट के पैराग्राफ 101 में इस प्रकार रखा गया था:

> "101. उपरोक्त निर्णयों से हमें पता चलता है कि केवल हत्या की क्रूरता या मारे गए व्यक्तियों की संख्या या जिस तरीके से शव को

ठिकाने लगाया गया है, वह हमेशा इस न्यायालय को मौत की सजा देने के लिए राजी नहीं करता है। इसी तरह, कभी-कभी, अजीबोगरीब मामले भी सामने आते हैं। तथ्यात्मक मैट्रिक्स, इस न्यायालय ने फैसला देना उचित नहीं समझा है। उन मामलों में मृत्युदंड, जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित थे या केवल अनुमोदक के साक्ष्य पर। जहां हत्या, क्रूर होते हुए भी, अत्यधिक भावनात्मक अशांति से प्रेरित होकर की जाती है और इसका अनुपात बहुत बड़ा नहीं होता है, वहां कुछ मामलों में आजीवन कारावास के विकल्प का प्रयोग किया गया है.....(जोर हमारे द्वारा दिया गया है)।

28. अंत में, कालू खान बनाम राजस्थान राज्य ((2015) 16 एससीसी 492) में इस न्यायालय ने स्वामी श्रद्धानंद का उल्लेख किया और रिपोर्ट के पैराग्राफ 31 में, मामले के तथ्यों पर यह माना गया कि परिस्थितियों का संतुलन "दोषी गणना" में अनिश्चितता का परिचय देता है। और इसलिए मृत्युदंड लगाने का एक विकल्प था। तदनुसार, सज़ा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया।

29. उपरोक्त चर्चा का परिणाम यह है कि सामान्यतः परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में मृत्युदंड देना उचित नहीं होगा। लेकिन ऐसा कोई सख्त नियम नहीं है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में मौत की सज़ा नहीं दी जानी चाहिए। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामलों में सभी अदालतों द्वारा बरती जाने वाली सावधानियां इस प्रकार हैं: यदि अदालत को रिकॉर्ड पर परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर कुछ संदेह है, कि अभियुक्त ने अपराध नहीं किया होगा, तो बरी करने का मामला बनाया जाएगा। बाहर; यदि अदालत को परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर कोई संदेह नहीं है कि अभियुक्त दोषी है, तो निश्चित रूप से दोषसिद्धि होनी चाहिए। यदि अदालत मौत की सज़ा देने के लिए

इच्छुक है तो कुछ असाधारण परिस्थितियाँ होनी चाहिए जो अत्यधिक सज़ा देने के लिए आवश्यक हों। ऐसे मामलों में भी, अदालत को बचन सिंह मामले में दी गई उक्ति का पालन करना चाहिए कि न केवल अपराध, बल्कि अपराधी को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए और सजा का कोई भी वैकल्पिक विकल्प निर्विवाद रूप से बंद है। दूसरी सावधानी का कारण यह है कि फाँसी पर मौत की सज़ा अपरिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय है।

30. जहां तक वर्तमान मामले का सवाल है, अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने केवल रिकॉर्ड पर परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने पर ज्यादा जोर नहीं दिया। इसलिए, हमें अपराध की प्रकृति और अन्य कारकों की जांच करने या इस संबंध में खुद को हिरासत में लेने की आवश्यकता नहीं है। हमने केवल रिकॉर्ड की पूर्णता के लिए और इस दृष्टिकोण की पुष्टि करने के लिए विद्वान वकील द्वारा उद्धृत विभिन्न निर्णयों का उल्लेख किया है कि आम तौर पर दोषसिद्धि के आधार पर परिस्थितिजन्य साक्ष्य मौत की सजा नहीं दी जानी चाहिए।

सुधार, पुनर्वास और समाज में पुनः एकीकरण

31. किसी दोषी के सुधार या पुनर्वास पर चर्चा बचन सिंह की इस स्वीकारोक्ति से शुरू होती है कि यह संभावना कि एक दोषी को सुधारा और पुनर्वासित किया जा सकता है, यह तय करने के लिए एक वैध विचार है कि उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास दिया जाना चाहिए या नहीं। इस न्यायालय ने इस दृष्टिकोण को भी स्वीकार किया है कि साक्ष्य द्वारा यह साबित करना राज्य का काम है कि दोषी सुधार और पुनर्वास के योग्य नहीं है और इसलिए, उसे मौत की सजा दी जानी चाहिए।

32. इस दृष्टिकोण को उन सभी निर्णयों में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया है जो अपीलकर्ता के वकील द्वारा हमारे सामने उद्धृत किए गए थे।

33. प्रकाश धवल खैरनार (पाटिल) बनाम महाराष्ट्र राज्य (2002) 2 एससीसी 35) में इस न्यायालय द्वारा दोषी के सुधार और पुनर्वास की संभावना पर विचार किया गया था। यह माना गया था कि दोषी की कोई आपराधिक प्रवृत्ति नहीं थी और वह लाभप्रद रूप से कार्यरत था। हालांकि अपराध जघन्य था, यह मानना मुश्किल होगा कि यह दुर्लभतम मामलों में से एक था। यह नहीं माना जा सकता कि अपीलकर्ता समाज के लिए खतरा होगा और यह मानने का कोई कारण नहीं है कि उसे सुधार या पुनर्वास नहीं किया जा सकता है। तदनुसार, मृत्युदंड को 20 वर्ष के कारावास में बदल दिया गया

34. लेहना बनाम हरियाणा राज्य (2002) 3 एससीसी 76 में यह माना गया था कि मौत की सजा देने के विशेष कारण ऐसे होने चाहिए जो अदालत को यह निष्कर्ष निकालने के लिए मजबूर करें कि अपराधी को सुधारना और पुनर्वास करना संभव नहीं है। यह पैराग्राफ 14 में कहा गया था रिपोर्ट इस प्रकार है:

> 14 मौत की सज़ा को आम तौर पर खारिज कर दिया जाता है और इसे केवल "विशेष कारणों" से ही लगाया जा सकता है, जैसा कि धारा 354 (3) में दिया गया है। संहिता में एक और प्रावधान है जो महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति "विशेष कारण" का भी उपयोग करता है। यह धारा 361 है... धारा 361 जो कि संहिता में एक नया प्रावधान है, अदालत के लिए धारा 360 के प्रावधानों को लागू न करने के लिए "विशेष कारणों" को दर्ज करना अनिवार्य बनाता है। धारा 361 इस प्रकार प्रावधानों को लागू करने के लिए अदालत पर कर्तव्य डालती है। धारा 360 का जहां भी ऐसा करना संभव हो और यदि वह ऐसा नहीं करता है तो "विशेष कारण" बताएं। धारा 360 के संदर्भ में, धारा 361

द्वारा विचार किए गए "विशेष कारण" ऐसे होने चाहिए जो अदालत को यह मानने के लिए मजबूर करें कि अपराधी को सुधारना और पुनर्वास करना असंभव है।''

उम्र को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच की गई। अपराधी का चरित्र और पूर्ववृत्त और वे परिस्थितियाँ जिनमें अपराध किया गया था। यह विधायिका द्वारा कुछ संकेत है कि अपराधियों का सुधार और पुनर्वास, न कि केवल निवारण, अब हमारे देश में आपराधिक न्याय प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण वस्तुओं में से एक है। धारा 361 और धारा 354 (3) दोनों एक ही समय में क़ानून-पुस्तक में दर्ज हुई हैं और वे अपराध विज्ञान में नए रुझानों की विधायिका द्वारा स्वीकृति की उभरती तस्वीर का हिस्सा हैं। इसलिए, यह मान लेना गलत नहीं होगा कि अपराधी का व्यक्तित्व, जैसा कि उसकी उम्र, चरित्र, पूर्ववृत्त और अन्य परिस्थितियों से पता चलता है और अपराधी की सुधार के लिए सुगम्यता को आवश्यक रूप से दी जाने वाली सजा का निर्धारण करने में सबसे प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए। . विशेष कारणों का इन कारकों से कुछ संबंध अवश्य होना चाहिए... (जोर हमारे द्वारा दिया गया है)।

35. बरियार में इस न्यायालय ने बचन सिंह मामले में निर्धारित कानून का हवाला दिया कि मृत्युदंड केवल दुर्लभतम मामलों में ही दिया जाना चाहिए और फिर रिपोर्ट के पैराग्राफ 66 में कहा गया कि यह इंगित करने के लिए स्पष्ट सबूत होने चाहिए। दोषी सुधार और पुनर्वास में असमर्थ है। इसे इस प्रकार आयोजित किया गया:

"66. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, दुर्लभ से दुर्लभतम सूक्ति, मौत की सजा और आजीवन कारावास की वैकल्पिक सजा के बीच इस अंतर पर संकेत देती है। यहां प्रासंगिक प्रश्न यह निर्धारित करना होगा कि क्या सजा के रूप में आजीवन कारावास निरर्थक और पूरी तरह से तर्कहीन होगा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में? जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, आजीवन कारावास को पूरी तरह से निरर्थक कहा जा सकता है, केवल तभी जब सुधार के सजा लक्ष्य को अप्राप्य कहा जा सकता है। इसलिए, दुर्लभतम सिद्धांत के दूसरे अपवाद को संतुष्ट करने के लिए , अदालत को इस बात का स्पष्ट सबूत देना होगा कि दोषी किसी भी प्रकार की सुधारात्मक और पुनर्वास योजना के लिए उपयुक्त क्यों नहीं है। यह विश्लेषण केवल तभी कठोरता से किया जा सकता है जब अदालत अन्य परिस्थितियों के साथ-साथ अपराधी से संबंधित परिस्थितियों पर भी ध्यान केंद्रित करती है। इसे समझना आसान निष्कर्ष नहीं है, लेकिन बचन सिंह ने दुर्लभतम सिद्धांत का परिचय देकर मानक को बहुत ऊंचा स्थापित किया है।" (जोर हमारे द्वारा दिया गया)।

36. रमेश में रिपोर्ट के पैराग्राफ 69 में शिवाजी और बचन सिंह का संदर्भ दिया गया था और बरियार में व्यक्त विचार को दोहराते हुए यह कहा गया था कि किसी दोषी का सुधार और पुनर्वास सजा देने के उद्देश्यों के लिए एक कम करने वाली परिस्थिति है और राज्य को सबूतों के आधार पर यह साबित करना चाहिए कि दोषी के सुधरने की संभावना नहीं है।

37. संदेश बनाम महाराष्ट्र राज्य (2013) 2 एससीसी 479) में इस न्यायालय ने एक बार फिर इस सिद्धांत को स्वीकार किया कि अभियोजन पक्ष को यह दिखाने के

लिए सबूत पेश करना है कि ऐसी कोई संभावना नहीं है कि दोषी को सुधारा नहीं जा सकता है।

38. इसी प्रकार, मोहिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य (2013) 3 एससीसी 294) में रिपोर्ट के पैराग्राफ 23 में इसे इस प्रकार रखा गया था:

> "जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, आजीवन कारावास को पूरी तरह से निरर्थक तभी कहा जा सकता है, जब सुधार का सजा लक्ष्य अप्राप्य हो। इसलिए, "दुर्लभ से दुर्लभतम" सिद्धांत के दूसरे पहलू को संतुष्ट करने के लिए, अदालत को इस बात का स्पष्ट सबूत देना होगा कि दोषी किसी भी प्रकार की सुधारात्मक और पुनर्वास योजना के लिए उपयुक्त क्यों नहीं है।" (जोर हमारे द्वारा दिया गया है)।

39. बिरजू बनाम मध्य प्रदेश राज्य ((2014) 3 एससीसी 421) में इस न्यायालय ने अपराधियों की परिवीक्षा ई अधिनियम, 1958 के प्रावधानों का हवाला देकर दोषी के सुधार और पुनर्वास की संभावना पर विचार करने की आवश्यकता को समझाया, जहां एक दोषी को एक मामले में परिवीक्षा के तहत रखा जाता है। जहां सुधार की संभावना है. यह रिपोर्ट के पैराग्राफ 20 में आयोजित किया गया था:

> "20. वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने यह विचार किया कि इस बात की कोई संभावना नहीं है कि आरोपी हिंसा के आपराधिक कृत्य नहीं करेगा और समाज के लिए निरंतर खतरा बनेगा और इस बात की कोई संभावना नहीं होगी कि आरोपी को सुधारा जा सके। या पुनर्वास। अदालतें कुछ छोटे अपराधों में सुधारात्मक सिद्धांत लागू करती थीं और व्यक्तियों को दोषी ठहराते समय, अदालतें कभी-कभी आरोपियों को सीआरपीसी की धारा 360 और अपराधियों की परिवीक्षा

अधिनियम, 1958 की धारा 3 और 4 के संदर्भ में परिवीक्षा पर रिहा कर देती थीं। धारा 13 और 14 अधिनियम में परिवीक्षा अधिकारियों की नियुक्ति और निष्पादित किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति का प्रावधान है। अदालतें भी, धारा 4 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, परिवीक्षा अधिकारी से एक रिपोर्ट मांगती हैं। हमारे विचार में, जबकि उचित मामलों में सजा सुनाते समय, सीआरपीसी की धारा 235 (2) के तहत आरोपी की सुनवाई करते समय अदालतें प्रोबेशन अधिकारी से रिपोर्ट भी मांग सकती हैं। अदालतें तब जांच कर सकती हैं कि क्या आरोपी के किसी अपराध में शामिल होने की संभावना है या आरोपी के सुधार और पुनर्वास की कोई संभावना है।" (जोर हमारे द्वारा दिया गया है)।

40. अनिल बनाम महाराष्ट्र राज्य (2014) 4 एससीसी 69 में इस न्यायालय ने सुधार और पुनर्वास सिद्धांत को लागू किया। वास्तव में, रिपोर्ट के पैराग्राफ 33 में एक निर्देश जारी किया गया था कि आईपीसी की धारा 302 जैसे अपराधों से निपटते समय, आपराधिक अदालतें मांग कर सकती हैं यह निर्धारित करने के लिए एक रिपोर्ट कि क्या दोषी को सुधारा या पुनर्वासित किया जा सकता है। इस न्यायालय ने यह सुनिश्चित करना आपराधिक अदालतों के कर्तव्य पर गौर किया कि क्या दोषी को सुधारा और पुनर्वासित किया जा सकता है और यह राज्य का दायित्व है कि वह सुधार की संभावना के पक्ष और विपक्ष में सामग्री प्रस्तुत करे। और पुनर्वास। इसे इस प्रकार आयोजित किया गया:

33. बचन सिंह मामले में इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है, "इस बात की संभावना कि अभियुक्त हिंसा के आपराधिक कृत्य नहीं

करेगा, क्योंकि यह समाज के लिए एक निरंतर खतरा होगा, एक प्रासंगिक परिस्थिति है, जिसे सजा के निर्धारण में बहुत महत्व दिया जाना चाहिए .यह बात संतोष कुमार सतीशभूषण बरियार ने आगे व्यक्त की है. कई बार अदालतें सजा का निर्धारण करते समय किसी मामले विशेष के तथ्यों को देखते हुए यह मान लेती हैं कि आरोपी समाज के लिए खतरा होगा और ऐसा नहीं है. सुधार और पुनर्वास की संभावना, जबकि उन कारकों का पता लगाना अदालत का कर्तव्य है, और राज्य अभियुक्तों के सुधार और पुनर्वास की संभावना के पक्ष और विपक्ष में सामग्री प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है। अदालतें जिन तथ्यों से निपटती हैं, कोई दिया गया मामला, ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचने का आधार नहीं हो सकता है, जिसमें, जैसा कि पहले ही कहा गया है, अतिरिक्त सामग्री की आवश्यकता होती है। इसलिए, हम निर्देश देते हैं कि आपराधिक अदालतें, दोषसिद्धि के बाद आईपीसी की धारा 302 जैसे अपराधों से निपटते समय, उचित मामलों में, यह निर्धारित करने के लिए एक रिपोर्ट मंगवाएं कि क्या आरोपी को सुधारा जा सकता है या उसका पुनर्वास किया जा सकता है, जो प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है।" (हमारे द्वारा दिया गया जोर)।

41. महेश धनाजी शिंदे बनाम महाराष्ट्र राज्य (2014) 4 एससीसी 292) में इस न्यायालय ने दोषियों के आचरण पर विचार किया और उसके समक्ष तथ्यों पर, यह निष्कर्ष निकाला कि यदि उन्हें समाज में पुनर्वासित किया जाता है तो वे एक परिवर्तित जीवन जीने में सक्षम हैं। किसी भी घटना में, राज्य ने यह तर्क नहीं दिया था कि दोषी सुधार से परे थे और यदि उन्हें समाज में पुनर्वासित किया जाता है तो वे एक परिवर्तित जीवन नहीं जी सकते।

42. सुशील शर्मा मामले में इस न्यायालय ने माना कि विभिन्न कारकों में से, मृत्युदंड देने या न देने के लिए विचार किए जाने वाले कारकों में से एक दोषी के सुधार और पुनर्वास की संभावना है। यह स्वीकारोक्ति रिपोर्ट के पैराग्राफ 103 में की गई थी, जिसमें कहा गया था:

> "103. चीजों की प्रकृति में, ऐसे कोई सख्त नियम नहीं हो सकते हैं जिनका पालन अदालत यह विचार करते समय कर सके कि किसी आरोपी को मौत की सजा दी जानी चाहिए या नहीं। एक आपराधिक मामले का मूल उसके तथ्य और तथ्य हैं हर मामले में अलग-अलग होता है। इसलिए, विभिन्न कारक जैसे अपराधी की उम्र, उसकी सामाजिक स्थिति, उसकी पृष्ठभूमि, क्या वह एक पुष्ट अपराधी है या नहीं, क्या उसका कोई पूर्ववृत्त था, क्या उसके सुधार और पुनर्वास की कोई संभावना है। या क्या यह ऐसा मामला है जहां सुधार असंभव है और आरोपी के भविष्य में फिर से ऐसे अपराध करने और समाज के लिए खतरा बनने की संभावना है, ये ऐसे कारक हैं जिनकी आपराधिक अदालत को प्रत्येक मामले में स्वतंत्र रूप से जांच करनी होगी। मौत की सजा दी जाए या नहीं, इसका निर्णय प्रत्येक मामले के तथ्यों और संबंधित परिस्थितियों में इस न्यायालय की कई आधिकारिक घोषणाओं में निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांतों के आलोक में जुर्माना लगाया जाना चाहिए या नहीं।" (जोर हमारे द्वारा दिया गया)।

43. इस स्तर पर, हमें बचन सिंह को याद करना चाहिए और सुधार और पुनर्वास की संभावना, संभाव्यता और असंभवता के बीच अंतर करना चाहिए। बचन सिंह हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम सुधार और पुनर्वास की संभावना पर विचार करें, न कि

इसकी संभावना या इसकी असंभवता पर।

44. अंत में, इस न्यायालय के एक हालिया निर्णय में, छन्नू लाल वर्मा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य 2018 की आपराधिक अपील संख्या 1482-1483 [एस.एल.पी से बाहर। (आपराधिक) संख्या 5898-5899/2014] 28 नवंबर 2018 को निर्णय लिया गया। जिन मामलों में मृत्युदंड दिए जाने की संभावना है, वहां दोषी के सुधार और पुनर्वास की संभावना पर जोर दिया गया। इसे रिपोर्ट के पैराग्राफ 15 में इस प्रकार रखा गया था:

> "15 अपराध की असामान्य प्रकृति या अपीलकर्ता के सुधार या पुनर्वास की अनुचितता के बारे में कोई सबूत पेश नहीं किया गया है। बचन सिंह (सुप्रा) स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मृत्युदंड केवल दुर्लभतम मामलों में ही दिया जाएगा, जहां अपराध की प्रकृति और अपराधी से संबंधित परिस्थितियों के कारण आजीवन कारावास पूरी तरह से अपर्याप्त या निरर्थक होगा। मृत्युदंड देते समय यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि व्यक्ति सुधार और पुनर्वास के लिए सक्षम है या नहीं.....(हमारे द्वारा दिया गया जोर)।

45. इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों द्वारा निर्धारित कानून स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से आदेश देता है कि किसी दोषी को सुधारा जा सकता है और समाज में उसका पुनर्वास किया जा सकता है, इसकी संभावना (संभावना या असंभाव्यता या असंभवता नहीं) को मृत्युदंड देने से पहले अदालतों द्वारा गंभीरता से और ईमानदारी से विचार किया जाना चाहिए। वाक्य। यह सीआरपीसी की धारा 354 (3) की "विशेष कारणों" की आवश्यकता के आदेशों में से एक है। और इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति का जीवन बर्बाद करना शामिल है। इस आदेश को

क्रियान्वित करने के लिए, अभियोजन पक्ष का यह दायित्व है कि वह साक्ष्य के माध्यम से अदालत को यह साबित करे कि संभावना यह है कि दोषी को सुधारा या पुनर्वासित नहीं किया जा सकता है। इसे अन्य बातों के साथ-साथ, जेल में उसके आचरण के बारे में सामग्री, अगर वह कुछ समय के लिए जमानत पर है तो जेल के बाहर उसका आचरण, उसकी मानसिक स्थिति के बारे में चिकित्सा साक्ष्य, उसके परिवार के साथ संपर्क आदि के बारे में सामग्री लाकर हासिल किया जा सकता है। इसी तरह दोषी इन मुद्दों पर भी सबूत पेश कर सकता है।

46. यदि इस प्रकृति की जांच की जानी है, जैसा कि इस न्यायालय के निर्णयों द्वारा अनिवार्य है, तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि दोषसिद्धि की तारीख और सजा देने की तारीख के बीच की अवधि पार्टियों को सक्षम करने के लिए काफी लंबी होगी। सबूत इकट्ठा करें और उनका नेतृत्व करें जो ट्रायल कोर्ट को सजा पर एक सूचित निर्णय लेने में सहायता कर सके। जी लेकिन, इस संबंध में कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि किसी भी मामले में दोषी काफी लंबे समय तक हिरासत में रहेगा और कम से कम आजीवन कारावास की सजा काटेगा।

47. दोषी के सुधार, पुनर्वास और पुनः समाज में एकीकरण पर विचार पर अधिक जोर नहीं दिया जा सकता। बचन सिंह तक, अदालतों द्वारा मुख्य रूप से अपराध की प्रकृति, उसकी क्रूरता और गंभीरता पर जोर दिया जाता था। बचन सिंह ने सजा प्रक्रिया को परिप्रेक्ष्य में रखा और दोषी के सुधार या पुनर्वास पर विचार करने की आवश्यकता का परिचय दिया। संविधान पीठ द्वारा व्यक्त किए गए विचार के बावजूद, ऐसे कई उदाहरण हैं, जिनमें से कुछ बरियार और संगीत बनाम हरियाणा राज्य (2013) 2 एससीसी 452) में बताए गए हैं, जहां अपराध को प्रधानता देने और कुछ हद तक अपराधी पर विचार करने की प्रवृत्ति है। द्वितीयक ढंग. जैसा कि संगीत में कहा गया है,

"सज़ा देने की प्रक्रिया में, अपराध और अपराधी दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। इसलिए, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अपराधी, चाहे वह कितना भी क्रूर क्यों न हो, फिर भी एक इंसान है और गरिमापूर्ण जीवन का हकदार है।" उसका अपराध इसलिए, यह निर्धारित करना अभियोजन और अदालतों का काम है कि क्या ऐसे व्यक्ति को, उसके अपराध के बावजूद, सुधार और पुनर्वास किया जा सकता है। इस जानकारी को प्राप्त करना और उसका विश्लेषण करना निश्चित रूप से एक आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी इसे पूरा किया जाना चाहिए। की प्रक्रिया पुनर्वास भी आसान नहीं है क्योंकि इसमें अपराधी का समाज में पुनः सामाजिक एकीकरण शामिल होता है। बेशक, उपलब्ध कराई गई किसी भी जानकारी और रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों के साथ विशेषज्ञों द्वारा उसके विश्लेषण के बावजूद, ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जहां सामाजिक पुनर्एकीकरण नहीं हो पाता है। दोषी की सजा संभव नहीं हो सकती है। यदि ऐसा होता है, तो लंबी अवधि के कारावास का विकल्प स्वीकार्य है।

48. दूसरे शब्दों में, 14 वर्ष (जैसे कि 20 या 25 वर्ष) से अधिक की अवधि के लिए कारावास का निर्देश देना निर्विवाद रूप से मौत की सजा देने से रोक सकता है, जो मृत्युदंड का एक वैकल्पिक विकल्प है।

डीएनए साक्ष्य

49. हालांकि सीआरपीसी की धारा 53-ए अनिवार्य नहीं है, लेकिन इसमें निश्चित रूप से एक सकारात्मक निर्णय लेने की आवश्यकता है। यह विश्वास करने के लिए उचित आधार होना चाहिए कि किसी व्यक्ति की जांच से बलात्कार के अपराध या बलात्कार करने के प्रयास के सबूत मिलेंगे। यदि उचित आधार मौजूद हैं, तो सीआरपीसी की धारा 53-ए (2) के अनुसार एक चिकित्सा जांच की जानी चाहिए। आयोजित किया जाना चाहिए और इसमें अभियुक्तों की जांच और वहां से ली गई

सामग्री का विवरण शामिल है डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए आरोपी का व्यक्ति। दूसरे दृष्टिकोण से देखें, यदि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि अभियुक्त की जांच से ऊपर उल्लिखित अपराध के कमीशन के बारे में सबूत नहीं मिलेंगे, तो यह काफी संभावना नहीं है कि बलात्कार या बलात्कार के प्रयास का अपराध करने के आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र भी दायर किया जाएगा।

50. इसी प्रकार धारा 164-ए सी.आर.पी.सी. जहां भी संभव हो, टेप के पीड़ित की चिकित्सीय जांच के लिए, निश्चित रूप से, पीड़ित की सहमति आवश्यक है और परीक्षा आयोजित करने वाला व्यक्ति पीड़ित की चिकित्सकीय जांच करने में सक्षम होना चाहिए। दुबारा, चिकित्सा परीक्षण की आवश्यकताओं में से एक पीड़ित की जांच और डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए महिला के शरीर से ली गई सामग्री का विवरण है।

51. इसमें कोई संदेह नहीं है कि फोरेंसिक विज्ञान और वैज्ञानिक जांच में उल्लेखनीय तकनीकी प्रगति हुई है। इनका पूरी तरह से उपयोग किया जाना चाहिए और कृष्ण कुमार मलिक बनाम हरियाणा राज्य (2011) 7 एससीसी) में जांच के कुछ हद तक पुराने तरीकों को छोड़ दिया जाना चाहिए" इस न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 53-ए का उल्लेख किया और देखा कि इसके अधिनियमन के बाद 23 जून, 2006 से प्रभावी प्रावधान "इस प्रकार के मामलों में अभियोजन पक्ष के लिए डीएनए परीक्षण कराना आवश्यक हो गया है, जिससे अभियोजन पक्ष को आरोपी के खिलाफ अपना मामला साबित करने में सुविधा होगी।"

52. वैज्ञानिक जांच में प्रगति का लाभ उठाने की आवश्यकता गुजरात राज्य बनाम किशनभाई मामले में चर्चा का विषय थी। उस मामले में, इस न्यायालय ने वैज्ञानिक जांच का लाभ उठाने में जांच एजेंसी की विफलता पर अफसोस जताया था:

"12.7.5. मामले के तात्कालिक पहलू पर वैज्ञानिक जांच में अब काफी प्रगति हुई है. जांच एजेंसी को रक्त के नमूनों की डीएनए प्रोफाइलिंग मांगनी चाहिए थी, जिससे यह स्पष्ट तस्वीर मिल जाती कि खून है या नहीं पीड़िता (हटाई गई) वास्तव में प्रतिवादी आरोपी किशनभाई के कपड़ों पर थी। इस वैज्ञानिक जांच ने निर्विवाद रूप से यह निर्धारित किया होगा कि प्रतिवादी-अभियुक्त है या नहीं अपराध से जुड़ा था। इसके अतिरिक्त, अपराध को अंजाम देने में इस्तेमाल किए गए चाकू पर पाए गए खून की डीएनए प्रोफाइलिंग की जाएगी (जिसे प्रतिवादी-अभियुक्त किशनभाई ने कथित तौर पर दिनेश भाई करसन भाई ठाकोर, पीडब्लू 6 से चुराया था)। यह निर्विवाद रूप से निर्धारित किया गया है कि क्या उक्त चाकू का उपयोग पीड़िता के पैरों को काटने के लिए किया गया था [हटा दिया गया], उसकी पायल उतारने के लिए किया गया था या नहीं।

12.7.6. फोरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में इतनी प्रगति के बावजूद, जांच एजेंसी ने प्रतिवादी-अभियुक्त किशनभर (हमारे द्वारा दिया गया जोर) की दोषीता को सही मायने में निर्धारित करने के लिए प्रभावी जांच नहीं करने में गंभीर गलती की।

53. अभी हाल ही में, मुकेश और अन्य बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) (2017) 6 एससीसी 1) में सीआरपीसी की धारा 53-ए और धारा 164-ए का एक संक्षिप्त संदर्भ है। इस संक्षिप्त संदर्भ में जो महत्वपूर्ण है वह यह स्वीकारोक्ति है कि अदालतों द्वारा डीएनए साक्ष्य पर तेजी से भरोसा किया जा रहा है। इसे पैराग्राफ 216 और 217 में इस प्रकार देखा गया:

"216. हमारे देश में भी कई अन्य विकसित और विकासशील देशों की तरह, अदालतों द्वारा डीएनए साक्ष्य पर तेजी से भरोसा किया जा रहा है। 2005 के अधिनियम 25 द्वारा धारा 53ए को सम्मिलित करके आपराधिक प्रक्रिया संहिता में संशोधन के बाद, डीएनए प्रोफाइलिंग अब वैधानिक योजना का एक पक्ष बन गया है। धारा 53ए एक चिकित्सक द्वारा बलात्कार के आरोपी व्यक्ति की जांच से संबंधित है।"

"217. इसी तरह, 2005 के अधिनियम 25 द्वारा डाली गई धारा 164ए के तहत, बलात्कार की पीड़िता की मेडिकल जांच के लिए, डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए महिला के चेहरे से ली गई सामग्री का विवरण आवश्यक है।" (हमारे द्वारा दिया गया जोर)।

54. अभियोजन पक्ष के लिए डीएनए साक्ष्य पेश करने से इनकार करना थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा, खासकर तब जब देश में डीएनए प्रोफाइलिंग की सुविधा उपलब्ध है। अभियोजन पक्ष को इसका लाभ उठाने की सलाह दी जाएगी, विशेष रूप से सीआरपीसी की धारा 53-ए सी और धारा 164-ए के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए। हम यह सुझाव देने की सीमा तक नहीं जा रहे हैं कि यदि डीएनए प्रोफाइलिंग नहीं है, तो अभियोजन पक्ष ऐसा नहीं कर सकता साबित किया जाए, लेकिन हमारा निश्चित तौर पर मानना है कि जहां डीएनए प्रोफाइलिंग नहीं की गई है या इसे ट्रायल कोर्ट से रोक दिया गया है, तो अभियोजन के लिए प्रतिकूल परिणाम होंगे।

55. मुकेश में न्यायमूर्ति भानुमति द्वारा एक अलग राय दी गई थी और रिपोर्ट के पैराग्राफ 455 में यह माना गया था कि डीएनए प्रोफाइलिंग नमूनों की तुलना करने का एक बेहद सटीक तरीका है और इस तरह के परीक्षण वस्तुतः सकारात्मक पहचान कर सकते हैं। यह कहा गया था:

"455. डीएनए प्रोफाइलिंग किसी संदिग्ध के डीएनए की तुलना अपराध स्थल के नमूनों, आरोपी के खून से सने कपड़ों पर पीड़ित के डीएनए या अन्य वस्तुओं से करने का एक बेहद सटीक तरीका है। बरामद, डीएनए परीक्षण लगभग सकारात्मक पहचान कर सकता है जब दोनों नमूने मेल खाते हैं डीएनए फिंगर प्रिंट शरीर के हर हिस्से के लिए समान होता है, चाहे वह रक्त, लार, मस्तिष्क, किडनी या शरीर के किसी भी हिस्से पर पैर हो, इसे बदला नहीं जा सकता, चाहे कुछ भी किया जाए यह एक समान होगा। शरीर। यहां तक कि अपराध स्थल पर या कपड़ों पर रक्त, लार या वीर्य की अपेक्षाकृत कम मात्रा भी विश्लेषण के लिए पर्याप्त सामग्री प्राप्त कर सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि पहचान लगभग सौ प्रतिशत सटीक है। इसका उपयोग करके आनुवंशिक जानकारी की रासायनिक संरचना उत्पन्न की जाती है। किसी व्यक्ति की डीएनए प्रोफ़ाइल, किसी व्यक्ति की पहचान अपराधियों की उंगलियों के निशान की पहचान करने की पारंपरिक पद्धति की तरह की जाती है।" (द्वारा जोर दिया गया है।)

56. वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के महत्व के संदर्भ में, हम सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य (2010) 7 एससीसी 263) मामले में रिपोर्ट के पैराग्राफ 220 में इस न्यायालय की टिप्पणी को याद कर सकते हैं कि "डीएनए नमूनों का मिलान एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उभर रहा है। संदिग्धों को विशिष्ट आपराधिक कृत्यों से जोड़ने के लिए।"

57. जहां तक हमारे समक्ष वर्तमान याचिकाओं का संबंध है, इसमें कोई विवाद नहीं है कि आरोपी के शरीर से नमूने लिए गए थे और डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए भेजे

गए थे। हालाँकि, परिणाम ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसके लिए बिल्कुल कोई स्पष्टीकरण नहीं है और डीएनए सबूत पेश न करने के किसी औचित्य के अभाव में, हमारा विचार है कि इस मामले के तथ्यों के आधार पर, अपीलकर्ता की मौत की सजा को बरकरार रखना खतरनाक होगा।

दोषी का पूर्व इतिहास या आपराधिक इतिहास -

58. दोषी का इतिहास, जिसमें दोबारा अपराध करना भी शामिल है, मौत की सज़ा देने का आधार नहीं हो सकता। इसके लिए कुछ स्पष्टता की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति हो सकती है जहां किसी दोषी ने पहले कोई अपराध किया हो और उसे उस अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो और सजा सुनाई गई हो। इसके बाद, दोषी दूसरा अपराध करता है जिसके लिए उसे दोषी ठहराया जाता है और सजा दिए जाने की आवश्यकता होती है। इससे कोई कानूनी चुनौती या कठिनाई उत्पन्न नहीं होती। लेकिन, ऐसी स्थिति भी हो सकती है जहां किसी दोषी ने अपराध किया हो और उस अपराध के लिए मुकदमा चल रहा हो। मुकदमे के लंबित रहने के दौरान वह दूसरा अपराध करता है। जिसके लिए उसे दोषी ठहराया जाता है और जिसमें सजा दिए जाने की आवश्यकता होती है।

59. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 54 पिछले बुरे चरित्र के साक्ष्य के उपयोग पर रोक लगाती है, सिवाय इसके कि जब दोषी स्वयं अपने अच्छे चरित्र का साक्ष्य देने का विकल्प चुनता हो। इसका तात्पर्य स्पष्ट रूप से यह है कि निर्दिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर, सजा की मात्रा निर्धारित करने के प्रयोजनों के लिए दोषी के पिछले प्रतिकूल आचरण पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

60. इस सामान्य नियम के कुछ अपवाद हैं। उदाहरण के लिए, आईपीसी की धारा 376-ई इस प्रकार प्रदान करती है:

"376ई. बार-बार अपराध करने वालों के लिए सजा - जो कोई भी पहले धारा 376 या धारा 376-ए या धारा 376एबी, या धारा 376डी या धारा 376डीए या धारा 376डीबी के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो और बाद में इनमें से किसी के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो। उक्त धाराओं में आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा जिसका अर्थ उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास या मौत होगी।"

61. इसी प्रकार, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 16 (2) निम्नानुसार प्रदान करती है:

''16. दंड. -

(1) XXX XXX XXX

(2) यदि इस अधिनियम के तहत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया कोई भी व्यक्ति बाद में इसी तरह का अपराध करता है तो यह उस अदालत के लिए वैध होगा जिसके समक्ष दूसरी या बाद की सजा होती है, अपराधी का नाम और निवास स्थान, अपराध और अपराधी के खर्च पर ऐसे समाचार पत्रों में या ऐसे अन्य तरीके से प्रकाशित करने के लिए जुर्माना लगाया जाएगा जैसा अदालत निर्देशित कर सकती है। ऐसे प्रकाशन के खर्च को दोषसिद्धि में शामिल होने की लागत का हिस्सा माना जाएगा और जुर्माने के समान ही वसूल किया जाएगा।"

62. अंत में, आईपीसी की धारा 75 का उल्लेख करना उचित है जो पिछली सजा के बाद आईपीसी के अध्याय XII या अध्याय XVII के तहत कुछ अपराधों के लिए बढ़ी हुई सजा का प्रावधान करता है। यह अनुभाग इस प्रकार है:

> "75. पिछली दोषसिद्धि के बाद अध्याय XII या अध्याय XVII के तहत कुछ अपराधों के लिए बढ़ी हुई सज़ा.- जो कोई भी दोषी ठहराया गया हो,-(ए) भारत में एक न्यायालय द्वारा, इस संहिता के अध्याय XII या अध्याय XVII के तहत तीन साल या उससे अधिक की अवधि के कारावास के साथ दंडनीय अपराध।
>
> इनमें से किसी भी अध्याय के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का दोषी होगा, समान अवधि के लिए कारावास, ऐसे प्रत्येक बाद के अपराध के लिए आजीवन कारावास, या किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है, के अधीन होगा।"

63. भारतीय विधि आयोग की 42 वीं रिपोर्ट में आईपीसी की धारा 75 के दायरे की चर्चा निम्नलिखित शब्दों में की गई है:

> "[यह] आदतन अपराधियों और दोबारा अपराध करने की समस्या से निपटने का एक प्रयास है। अन्य दंड प्रणालियों ने भी इस जटिल समस्या से निपटने की कोशिश की है, लेकिन कहीं भी प्रयासों को उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली है, शायद इसलिए कि अपराध के कारण स्वयं जटिल हैं क्योंकि पिछली सजा अपराधी को सुधारने के अपने उद्देश्य और उसे अपराध से रोकने के अपने उद्देश्य दोनों में विफल रही है, कानून, अंतिम उपाय के रूप में, उसे लंबे समय तक

जेल भेजकर अपराधी से समाज की रक्षा करने पर ध्यान केंद्रित करता है। पहले से अधिक अवधि।"

64. यह ध्यान देने योग्य है कि ऊपर उद्धृत कानून के तीन प्रावधान उन मामलों से संबंधित हैं जहां पूर्व दोषसिद्धि है और किसी अपराध से जुड़े मामले की लंबित सुनवाई से संबंधित नहीं हैं। इसलिए, हालाँकि दोषसिद्धि के बाद उसी अपराध की पुनरावृत्ति के लिए क़ानून द्वारा प्रदान की गई बढ़ी हुई सज़ा देना संभव है, लेकिन जहाँ क़ानून मौन है, वहाँ बढ़ी हुई सज़ा देने की संभावना उत्पन्न नहीं होती है, नतीजतन, यह माना जाना चाहिए कि के संदर्भ में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 54 के तहत किसी दोषी का पूर्ववृत्त सजा देने के प्रयोजनों के लिए प्रासंगिक नहीं है, जब तक कि दोषी अपने अच्छे चरित्र का सबूत नहीं देता।

65. मोहम्मद साहब में लंबित मुकदमे की तुलना में दोषसिद्धि के महत्व पर जोर दिया गया था। फारूक अब्दुल गफूर बनाम महाराष्ट्र राज्य (2009) 15 एससीसी 635 जिसमें निर्दोषता की धारणा को मानव अधिकार के रूप में विज्ञापित किया गया था और इसे रिपोर्ट के पैराग्राफ 178 में रखा गया था:

"178. हमारी राय में ट्रायल कोर्ट ने इस तथ्य को गलत तरीके से खारिज कर दिया था कि भले ही आरोपियों का आपराधिक इतिहास था, लेकिन उक्त तीनों आरोपियों के खिलाफ कोई आपराधिक दोषसिद्धि नहीं हुई थी। उसने उक्त तर्क को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि दोषसिद्धि हो सकती है प्रत्येक आपराधिक मुकदमे में यह संभव नहीं है। हमारी राय में जब तक कोई व्यक्ति दोषी साबित नहीं हो जाता, उसे निर्दोष माना जाना चाहिए। इसके अलावा, इतने वर्षों के बाद भी राज्य की ओर से उन आपराधिक मुकदमों में कुछ भी नहीं

लाया गया है जो चल रहे थे। अभियुक्तों के खिलाफ लंबित मामलों के परिणामस्वरूप उन्हें दोषी ठहराया गया। जब तक कि इसे रिकॉर्ड पर दस्तावेजों द्वारा नहीं दिखाया जाता है, हम इसके विपरीत मानेंगे। निर्दोषता की धारणा एक मानव अधिकार है। विद्वान परीक्षण न्यायाधीश को भी तीनों अभियुक्तों के खिलाफ यही धारणा बनानी चाहिए थी . हमारी राय में आरोपियों के कथित आपराधिक इतिहास का ट्रायल कोर्ट द्वारा तीनों आरोपियों को मौत की सजा देने पर बड़ा असर पड़ा। यही कारण है कि हमारी राय में उन्होंने इस संबंध में गलती की थी।" (जोर हमारे द्वारा दिया गया)।

66. हालाँकि, गुरमुख सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2009) 15 एससीसी 635 में, जबकि इस न्यायालय ने सजा के लिए एक कारक के रूप में दोषी के पूर्व इतिहास पर विचार या चर्चा नहीं की, रिपोर्ट के पैराग्राफ 23 में यह नोट किया गया कि पहले विचार के लिए प्रासंगिक कारकों में से एक दोषी को उचित सजा देने से उसके खिलाफ लंबित अन्य आपराधिक मामलों की संख्या बढ़ जाएगी। हमारी राय में, यह सही कानून नहीं बनाता है क्योंकि यह निर्दोषता की धारणा को नजरअंदाज करता है। इसे रिपोर्ट के पैराग्राफ 23 में इस प्रकार रखा गया था:

"23. ये कुछ कारक हैं जिन्हें आरोपी को उचित सजा देने से पहले ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। ये कारक केवल चरित्र में उदाहरणात्मक हैं और संपूर्ण नहीं हैं। प्रत्येक मामले को उसके विशेष परिप्रेक्ष्य से देखा जाना चाहिए। प्रासंगिक कारक इस प्रकार हैं अंतर्गत

(ए) से (जे) XXX XXX XXX

(के) आरोपियों के खिलाफ लंबित अन्य आपराधिक मामलों की संख्या,

(एल) से (एम) XXX XXX

ये कुछ कारक हैं जिन्हें आरोपी को उचित सजा देते समय ध्यान में रखा जा सकता है।" (हमारे द्वारा दिया गया जोर)।

67. बंटू बनाम म.प्र. राज्य (2001) 9 एससीसी 615) में इस न्यायालय ने कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि अपीलकर्ता का कोई आपराधिक इतिहास था, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि वह बड़े पैमाने पर समाज के लिए एक गंभीर खतरा होगा, इस तथ्य के बावजूद कि उसके द्वारा किया गया अपराध जघन्य था। इसे रिपोर्ट के पैराग्राफ 8 में इस प्रकार रखा गया था:

"8. हालाँकि, अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने कहा किसी भी परिस्थिति में, यह दुर्लभतम मामला नहीं है जहां आरोपी को मौत की सजा दी जानी है. उन्होंने वह सब्मिट कर दिया प्रासंगिक दिन पर आरोपी की उम्र 22 वर्ष से कम थी। यह उनका कहना है कि भले ही यह कृत्य जघन्य है, पर विचार किया जा रहा है तथ्य यह है कि मृतक के शरीर पर कोई चोट नहीं पाई गई है, यह संभव है कि उसका मुंह बंद करने से मौत हुई होगी और घटना के समय आरोपी द्वारा नोसेट्रिक्स [नासिका] का इस्तेमाल किया गया ताकि हो सकता है वह शोर न मचाये. उनके अनुसार मृत्यु, आकस्मिक और अनजाने में हुआ था। वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता को इंगित करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है। उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड था और न ही यह कहा जा सकता है कि उसका बड़े पैमाने पर समाज के लिए एक गंभीर ख़तरा होगा। यह सच है कि उनका कृत्य जघन्य है और इसकी निंदा की जानी चाहिए लेकिन साथ

ही यह भी नहीं कहा जा सकता कि यह दुर्लभ से भी दुर्लभतम है ऐसा मामला जहां आरोपी को बाहर निकालने की आवश्यकता है समाज। इसलिए, मृत्युदंड लगाने का कोई उचित कारण नहीं है वाक्य।" (जोर हमारे द्वारा दिया गया है)।

68. अमित बनाम महाराष्ट्र राज्य (2001) एससीसी 93) में इस न्यायालय ने अपीलकर्ता के पूर्व इतिहास की ओर ध्यान दिलाया और कहा कि पिछले किसी भी जघन्य अपराध का कोई रिकॉर्ड नहीं है और इस बात का भी कोई सबूत नहीं है कि अगर उसे मौत की सजा दी गई तो वह समाज के लिए खतरा होगा। उसे सम्मानित नहीं किया गया है। यह रिपोर्ट के पैराग्राफ 10 में आयोजित किया गया था:

"10. अगला प्रश्न सजा का है। यह देखते हुए कि अपीलकर्ता एक युवा व्यक्ति है, घटना के समय उसकी उम्र लगभग 20 वर्ष थी, वह एक छात्र था, पिछले किसी भी जघन्य अपराध का कोई रिकॉर्ड नहीं है और वहां भी इसका कोई सबूत नहीं है कि अगर मौत की सजा नहीं दी गई तो वह समाज के लिए खतरा होगा। हालांकि अपीलकर्ता द्वारा किया गया अपराध कड़ी निंदा का पात्र है और सबसे जघन्य अपराध है, लेकिन मामले के संचयी तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, हम ऐसा करते हैं। यह मत सोचिए कि यह मामला दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में आता है (जोर हमारे द्वारा दिया गया है)।

69. राहुल बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में इस न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्ता के आचरण के बारे में जेल अधिकारियों या परिवीक्षाधीन अधिकारी द्वारा कोई प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं थी और उसका कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था या कम से

कम न्यायालय के संज्ञान में कुछ भी नहीं लाया गया। रिपोर्ट के पैराग्राफ 4 में यह इस प्रकार देखा गया:

> "4. हमने मामले के सभी प्रासंगिक पहलुओं पर विचार किया है। यह सच है कि अपीलकर्ता ने बहुत ही भयानक तरीके से एक गंभीर अपराध किया है, लेकिन इस तथ्य पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि अपराध के समय उसकी उम्र 24 वर्ष थी। भले ही, अपीलकर्ता 27-11-1999 से हिरासत में था, हमें किसी भी परिवीक्षाधीन अधिकारी या जेल अधिकारियों द्वारा अपीलकर्ता के संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है। अपीलकर्ता का कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, और कुछ भी नहीं लाया गया था न्यायालय के संज्ञान में। यह नहीं कहा जा सकता कि वह भविष्य में समाज के लिए खतरा होगा। अपीलकर्ता की उम्र और अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमें नहीं लगता कि उसे मौत की सजा दी जाएगी।" (जोर हमारे द्वारा दिया गया)।

70. इसी प्रकार, सुरेंद्र पाल शिवबालकपाल बनाम गुजरात राज्य (2005) 3 एससीसी 127) में किसी भी पिछले आपराधिक मामले में किसी भी संलिप्तता की अनुपस्थिति को अपीलकर्ता को सजा देने के प्रयोजनों के लिए विचार करने योग्य कारक माना गया था। इसे रिपोर्ट के पैराग्राफ 13 में इस प्रकार रखा गया था:

> "13. अगला सवाल जो विचार के लिए उठता है वह यह है कि क्या यह "दुर्लभतम मामला" है; हमें नहीं लगता कि यह "दुर्लभतम मामला" है जिसमें अपीलकर्ता पर मौत की सजा दी जानी चाहिए। अपीलकर्ता था घटना के समय उसकी उम्र 36 वर्ष थी और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अपीलकर्ता पहले किसी अन्य आपराधिक

मामले में शामिल था और अपीलकर्ता यूपी का एक प्रवासी मजदूर था और विषम परिस्थितियों में रह रहा था और यह नहीं कहा जा सकता है कि वह होगा। यह भविष्य में समाज के लिए ख़तरा है और इस तरह का निष्कर्ष निकालने के लिए हमारे सामने कोई सामग्री नहीं रखी गई है। हमें नहीं लगता कि इस मामले में मृत्युदंड की आवश्यकता थी। हम सभी मामलों में अपीलकर्ता की दोषसिद्धि की पुष्टि करते हैं, लेकिन मृत्युदंड की सजा की पुष्टि नहीं करते हैं। आईपीसी की धारा 302 के तहत उस पर लगाए गए अपराध को आजीवन कारावास में बदल दिया गया है।" (हमारे द्वारा दिया गया जोर)

71. एक लंबित मुकदमे के विरुद्ध दोषसिद्धि का महत्व और महत्त्व कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय में चर्चा का विषय था। महामहिम द क्वीन बनाम नॉर्मन स्कोलनिक [1982] 2 एससीआर 47 कोक के संस्थानों में आंशिक रूप से इस आशय से "संशोधित" किया गया था कि किसी व्यक्ति को दूसरे अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने से पहले तीसरे अपराध के लिए सजा नहीं दी जा सकती है, न ही उस व्यक्ति को पहले दूसरे अपराध के लिए सजा दी जा सकती है। उन्हें पहले अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है। दूसरा अपराध पहली दोषसिद्धि के बाद किया जाना चाहिए और तीसरा अपराध दूसरी दोषसिद्धि के बाद किया जाना चाहिए। सिद्धांत यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त को बढ़े हुए दंड के खतरे का सामना नहीं करना पड़ता है जब तक कि उसे पहले दोषी नहीं ठहराया गया हो और सजा नहीं दी गई हो।

72. इसी प्रकार, स्कॉट नाथन श्लूटर बनाम रॉबिन लारेंस ट्रेनेरी (1997) 6 एनटीएलआर 194 मामले में ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र के सर्वोच्च न्यायालय ने विचार

किया कि वास्तविक कारावास की अवधि को बढ़ाना उचित हो सकता है। यदि अपराध का दूसरा पता चलता है। यदि अपराध की वह दूसरी खोज गायब है तो "एक से अधिक अपराधियों के लिए, जिन पर पहले आरोप नहीं लगाया गया है, प्रतिबंधित आपराधिक व्यवहार के लिए सजा की गंभीरता की निश्चितता के बारे में जागरूक होने का कोई अवसर नहीं होगा।"

73. इसलिए हमारे सामने रखे गए विभिन्न निर्णयों से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी दोषी के खिलाफ केवल एक या अधिक आपराधिक मामलों का लंबित होना सजा सुनाते समय विचार का कारक नहीं हो सकता है। न केवल यह वैधानिक रूप से अस्वीकार्य है (कुछ मामलों को छोड़कर) बल्कि अन्यथा यह निर्दोषता की मौलिक धारणा का उल्लंघन करता है - एक मानव अधिकार जिसका हर कोई हकदार है।

74. जहां तक वर्तमान मामले का सवाल है, यह रिकॉर्ड पर आया है कि अपीलकर्ता के खिलाफ समान अपराधों के लिए दो मामले लंबित हैं। इन दोनों पर मुकदमा चल रहा था। इसके बावजूद, ट्रायल जज ने इसे अपीलकर्ता के खिलाफ एक परिस्थिति के रूप में ध्यान में रखा। हमारी राय में, सत्र न्यायाधीश के लिए इंतजार करना कहीं अधिक उचित होता, अगर वह इन मामलों की सुनवाई को समाप्त करने के लिए लंबित मामलों पर विचार करना आवश्यक समझते। हमें पता होना चाहिए कि अपीलकर्ता पर दो मामले थोपे गए होंगे और अन्यथा वह दोषी नहीं साबित हो सकता था। हम आम तौर पर निष्कर्ष में उल्लेख कर सकते हैं कि वास्तव में ऐसा है।

75. ट्रायल जज के लिए ऐसे मामले में सजा देने में जल्दबाजी करने का कोई कारण नहीं है, जहां वह इस आधार पर मौत की सजा पर विचार कर रहा हो कि कोई अन्य वैकल्पिक विकल्प निर्विवाद रूप से बंद है। किसी भी मामले में दोषी को काफी लंबे समय तक हिरासत में रहना होगा क्योंकि दी जाने वाली न्यूनतम सजा आजीवन

कारावास होगी। इसलिए, एक ट्रायल जज अपना समय ले सकता है और अभियोजन पक्ष के साथ-साथ बचाव पक्ष को बचन सिंह मामले में बताई गई सामग्री पेश करने का पर्याप्त अवसर देने के बाद दोषी को सजा दे सकता है, ताकि ट्रायल जज के लिए आजीवन कारावास की सजा देने की संभावना खुली रहे। मौत की सज़ा. इस बात की सराहना की जानी चाहिए कि मौत की सजा केवल दुर्लभतम मामलों में ही दी जानी चाहिए, केवल तभी जब कोई वैकल्पिक विकल्प निर्विवाद रूप से बंद हो और सभी कारकों पर पूर्ण विचार करने के बाद ही यह ध्यान में रखा जाए कि मौत की सजा अपरिवर्तनीय है और निष्पादन पर अपरिवर्तनीय है। यह हमेशा याद रखना चाहिए कि जहां तक अपराध महत्वपूर्ण है, जहां तक सजा देने की प्रक्रिया का सवाल है, अपराधी भी उतना ही महत्वपूर्ण है। दूसरे शब्दों में, अदालतों को "आश्वासन को दोगुना सुनिश्चित करना चाहिए" शेक्सपियर की माचिस, अधिनियम IV, दृश्य।

76. हम यहां एक पोस्ट स्क्रिप्ट के माध्यम से नोट कर सकते हैं कि प्रस्तुतियाँ के दौरान, अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा यह कहा गया था कि इस बीच अपीलकर्ता को लंबित मामलों में से एक में दोषी ठहराया गया था, अर्थात राज्य महाराष्ट्र बनाम राजू और राजेंद्र निर्णय वासनिक (2007 का एस.टी. नं. 162)। इस मामले का फैसला 18 अप्रैल, 2016 को सत्र न्यायाधीश, अमरावती, महाराष्ट्र द्वारा किया गया था। ट्रायल जज ने दोषी पाए जाने पर अपीलकर्ता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि यह ध्यान में रखा कि वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता को मौत की सज़ा सुनाई गई थी।

77. सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी के ई-कोर्ट प्रोजेक्ट की वेबसाइट को देखने से पता चला कि वास्तव में अपीलकर्ता के खिलाफ कुल चार मामले थे, जिसमें वह मामला भी शामिल है जिससे हम निपट रहे हैं। एस.टी. में सत्र न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय के पैराग्राफ 38 में। 2007 की संख्या 162 में इसे इस प्रकार दर्ज किया गया था:

"[38] इस अपराध की पीड़िता की उम्र लगभग 9 से 10 वर्ष थी और अभियोजन पक्ष ने साबित कर दिया कि आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया था। तथ्यों और परिस्थितियों और रिकॉर्ड से ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस स्टेशन खोलापुरीगेट, अमरावती के अपराध संख्या 23/2007 में (एस.टी.नं.183/2007) आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 376(2)(1) और 377 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया और मौत की सजा सुनाई गई। उसे अपराध संख्या 31/2007 में भी दोषी ठहराया गया है। पुलिस स्टेशन दरियापुर 112/2007) और उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2) (एफ) के तहत दंडनीय अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। उन्हें पुलिस स्टेशन चिखलदरा, जिला अमरावती (S.T.No.66/2007) के अपराध संख्या 21/2006 में भी दोषी ठहराया गया है और उन्हें धारा 363, 366, 376 (2) के तहत दंडनीय अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। एफ), भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 201। में मौत की सज़ा 183/2007 की पुष्टि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक हो चुकी है और ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त द्वारा दायर दया याचिका भी भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा खारिज कर दी गई है। आरोपी ने एक ही प्रकृति का अपराध यानी नाबालिग और मासूम लड़की के साथ बलात्कार किया। यह उसी प्रकृति का उसका चौथा अपराध है जिसमें आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366 और 376 (2) (एफ) के तहत अपराध साबित हुआ है। यह ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने की आदत है।

अपराध की गंभीरता और तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय है कि अभियुक्त नरमी का पात्र नहीं है और मेरे अनुसार, निम्नलिखित सजा न्याय के उद्देश्य को पूरा करेगी..."

हमें यह सूचित नहीं किया गया है कि अपीलकर्ता के खिलाफ पारित सजा आदेश रद्द कर दिए गए हैं या नहीं। इसलिए हम एफ इस आधार पर आगे बढ़ रहे हैं कि अपीलकर्ता को वर्तमान मामले में मौत की सजा और उसके खिलाफ तय किए गए तीन अन्य मामलों में आजीवन कारावास की सजा दी गई है, जो अपीलीय अदालत द्वारा पारित किसी भी आदेश के अधीन है।

78. हालाँकि, हमें अपना आश्चर्य और पीड़ा व्यक्त करनी चाहिए कि अपीलकर्ता को एक से अधिक अवसरों पर उसके खिलाफ कथित अपराध करने का अवसर मिला। यह केवल तभी संभव हो सकता था यदि अपीलकर्ता जमानत पर होता और हमें आश्चर्य और पीड़ा यह है कि हमारे सामने तथ्यों की पृष्ठभूमि में, अपीलकर्ता को वास्तव में जमानत दे दी गई थी।

निष्कर्ष

79. जहां तक वर्तमान याचिका का संबंध है, हमारी राय है कि सजा के प्रयोजनों के लिए, सत्र न्यायाधीश, उच्च न्यायालय और साथ ही इस न्यायालय ने सुधार, पुनर्वास और सामाजिक पुन: एकीकरण की संभावना पर विचार नहीं किया। अपीलकर्ता को समाज में वास्तव में, इस संबंध में किसी भी तरह से किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए और इस मामले के तथ्यों के आधार पर किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अदालतों के समक्ष कोई सामग्री या सबूत नहीं रखा गया था। अभियोजन पक्ष ने उपलब्ध डीएनए साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने में लापरवाही बरती और भौतिक साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफलता के कारण अभियोजन पक्ष के खिलाफ और सजा के प्रयोजनों के लिए

अपीलकर्ता के पक्ष में प्रतिकूल धारणा बननी चाहिए। सजा सुनाने के प्रयोजनों के लिए, अपीलकर्ता के खिलाफ दो समान मामलों की लंबितता पर विचार करने में भी ट्रायल कोर्ट ने गलती की थी, जिस पर वह कानून के अनुसार विचार नहीं कर सकता था। हालाँकि, हम अपीलकर्ता के खिलाफ दो (वास्तव में तीन) समान मामलों के संबंध में बाद के घटनाक्रमों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते।

80. इन सभी कारणों से, हमारी राय है कि अपीलकर्ता और उसके द्वारा किए गए अपराधों को देखना अधिक उचित होगाअपीलकर्ता को दी गई मौत की सजा को कम करने के लिए उसके समग्र व्यक्तित्व और उसके बाद की घटनाओं सहित रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री, लेकिन निर्देश दें कि उसे उसके शेष सामान्य जीवन के लिए हिरासत से रिहा नहीं किया जाना चाहिए। हम तदनुसार ऑर्डर करते हैं।

81. याचिकाओं का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

दिव्या पांडे समीक्षा याचिकाएं निस्तारित

यह अनुवाद ए आई टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा मे समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अँग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।